DD
दिव्य दिल्ली
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र
RNI No. DLHIN/25/A2321
वर्षः 01, अंकः 10, पृष्ठः 08
infodivyadelhi@gmail.com
बुधवार, 17 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi
तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री सूर्योदय 05.25 सूर्यास्त 06.50

2047 का विजन तभी सफल, जब देश हो नशा मुक्तः शाह

नरेंद्र मोदी सरकार देश से ड्रग्स के खतरे को पूरी तरह मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित: अमित शाह

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश से ड्रग्स के खतरे को पूरी तरह मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित और महान राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस सपने को पूरा करने के लिए देश का सुरक्षित होना जरूरी है और सुरक्षा तभी संभव है जब युवा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की नींव होते हैं और यदि वे नशे की चपेट में आ जाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का पैमाना बड़ा किया जाए।

ड्रग्स के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ें

दुनिया के कई हिस्सों में यह देखा गया है कि किसी राष्ट्र की प्रगति और ड्रग्स की चुनौती का सीधा संबंध है।
दुर्भाग्य से, जिन दो क्षेत्रों से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई होती है, वे भारत के नजदीक हैं। इसलिए यह समय है कि हम इस खतरे के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ें।

ड्रग्स के तीन तरह के कार्टेल
शाह ने कहा कि ड्रग्स के कारोबार में तीन तरह के कार्टेल सक्रिय हैं। पहला, वे कार्टेल जो देश के एंट्री पॉइंट्स पर काम करते हैं। दूसरा, वे जो एंट्री पॉइंट से राज्यों तक सप्लाई नेटवर्क संभालते हैं। तीसरा, वे छोटे स्तर के कार्टेल जो पान की दुकानों और मोहल्लों तक ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्तरों पर सख्त प्रहार करना होगा और यह तभी संभव है जब अधिकारी इसे अपनी लड़ाई समझकर आगे बढ़ें।

विदेशी तस्करों पर कार्रवाई

गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स कारोबार में शामिल विदेश में बैठे अपराधियों को कानून के दायरे में लाना अब बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। शाह ने सभी प्रमुखों से अपील की कि वे सीबीआई से समन्वय कर प्रत्यर्पण की एक मजबूत व्यवस्था बनाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने अभय चौटाला को दी राहत

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता अभय चौटाला को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अभय चौटाला को 2008 में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में जारी समन रद्द कर दिया गया था।

क्या है मामला
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। अदालत रिटायर्ड अधिकारी परमवीर राठी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने अगस्त 2008 में चौटाला और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

देहरादून के कारलीगाढ़ में बाढ़ से तबाही, कई घर व दुकानें बही

देहरादून
उत्तराखंड में सोमवार रात भारी बारिश के चलते देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र के कारलीगाढ़ के किनारे कई घरों मलबा समा गया। पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा को भी नुकसान पहुंचा है। यहां कई दुकानें बह गई। सौंग नदी उफान पर है और इससे खतरा बना हुआ है। रायपुर केशर वाला में सड़क का करीब 90 मीटर हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालतप्पड़ क्षेत्र में सीमा डेंटल कॉलेज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत एवं बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। बारिश का क्रम मंगलवार को भी जारी है। सोमवार रात तेज बारिश के बाद देहरादून जिले आपदा की चपेट में है। रायपुर क्षेत्र में मालदेवता चौकी से आगे केशरवाला मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने व तेज बहाव के कटाव से सड़क का लगभग सस्ता 80-90 मीटर हिस्सा बह गया है, जिस कारण मार्ग पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया है।

इजराइल का गाजा में बड़ा जमीनी सैन्य अभियान शुरू

गाजा पट्टी। इजराइल ने गाजा में आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया है। इन हमलों में 41 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। गाजा शहर पर धीरे-धीरे नियंत्रण के साथ आगे बढ़ रही इजराइली सेना ने निवासियों से अन्यत्र चले जाने का आह्वान किया है।

'जीएसटी सुधारों से मिली छूटों का प्रमुखता से विज्ञापन करें'

नई दिल्ली
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के कारण खुदरा श्रृंखलाओं को मिली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और विज्ञापन देने का निर्देश दिया है।भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे गए पत्र में उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को रसीद/बिल में जीएसटी कटौती को जीएसटी छूट के रूप में दर्शाना चाहिए और अधिक प्रभाव वाले उत्पादों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
निर्देश में कहा गया, "अपने नेटवर्क के माध्यम से 'जीएसटी के कारण छूट' को प्रमुखता से प्रदर्शित और विज्ञापित करें।

पश्चिम विहार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया

शिवानी कौर बमराह
दिव्य दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार ए-2 में स्थित से सर्वोदय को-एड विद्यालय में दिल्ली सरकार द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाबी बाग रऊद अनिता यादव और शकूरबस्ती विधानसभा के विधायक करनैल सिंह उपस्थित रहे। इस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम विहार, मुल्तान नगर और पीरागढ़ी केम्प की जनता की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया गया। इस अवसर पर सभी फ्ह्ञअ प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के समकक्ष रखा। इस दौरान पंजाबी बाग की र्शे अनिता यादव और शकूरबस्ती विधानसभा के विधायक करनैल सिंह ने सभी की समस्याओं को सुना ताकि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकें।

महाराष्ट्रः 31 जनवरी 2026 तक निकाय चुनाव कराने का निर्देश

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस साल 10 अक्तूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि 6 मई को जारी उसके तर्कसंगत आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहा। तत्कालीन आदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर और चुनाव चार महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए समय सीमा में और विस्तार दे दिया है।

बेटिंग एप मामले में युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ईडी का समन

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए तलब किया है। उथप्पा को 22 सितंबर और युवराज को 23 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। उथप्पा फिलहाल एशिया कप 2025 की कमेंट्री टीम का हिस्सा हैं। दिल्ली में इस केस में अब तक चार पूर्व भारतीय क्रिकेटर तलब किए जा चुके हैं। इससे पहले, इस मामले में संघीय एजेंसी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की थी। यह मामला 1७ई३ नामक सट्टेबाजी एप प्लेटफॉर्म से जुड़ा है।

ईडी पूछताछ के दौरान यह समझना चाहती है कि क्रिकेटरों की इस एप में क्या भूमिका रही है या संबंध रहे हैं।

पीएम आज महिला स्वास्थ्य सेवाओं की करेंगे शुरूआत

पीएम मोदी जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा। देशभर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई अन्य पहलों का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देशभर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक क्लिक से सीधे धनराशि हस्तांतरित करेंगे। इससे देश की लगभग दस लाख महिलाओं को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। यह चैटबॉट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री राज्य के लिए एक करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे।

पीएम मोदी आदि सेवा पर्व' का भी शुभारंभ करेंगे

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ करेंगे, जो आदिवासी गौरव और राष्ट्र निर्माण की भावना के संगम का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। 2,150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि शामिल हैं, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाते हैं। यह क्षेत्र के कपास उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करके भी महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करेगा।

प्रधानमंत्री आज धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ करेंगे, जो आदिवासी गौरव और राष्ट्र निर्माण की भावना के संगम का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। 2,150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि शामिल हैं, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाते हैं। यह क्षेत्र के कपास उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करके भी महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करेगा। प्रधानमंत्री राज्य की एक बगिया माँ के नाम पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की एक लाभार्थी को एक पौधा भेंट करेंगे।

मध्य प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा महिलाएं माँ की बगिया विकसित करेंगी। महिला समूहों को पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान न भेजने के फैसले पर भगवंत मान ने ऐतराज जताया

चंडीगढ़

भारत सरकार की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान भेजने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि भाजपा की नीति पाकिस्तान के खिलाफ है या अपने ही लोगों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इससे मोदी सरकार का पंजाब विरोधी रवैया झलकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक पाकिस्तानी अभिनेत्री किसी पंजाबी अभिनेता के साथ फिल्म करती है, तो केंद्र सरकार उस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देती है और पंजाबियों को गद्दार करार देती है। भगवंत सिंह मान ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार से हमारी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी कलाकारों को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि, यह फिल्म पुलवामा आतंकी हमले से काफी पहले फिल्माई गई थी, लेकिन पुलवामा हमले के बहाने फिल्म पर प्रतिबंध लगाना सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की अनुमति केवल इसलिए दी जाती है, क्योंकि 'बड़े साहब' का बेटा यह मैच करवाना चाहता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर भारत, पाकिस्तान के साथ मैच खेल हो सकता है, तो श्रद्धालु श्री करतारपुर साहिब और श्री ननकाना साहिब माथा टेकने क्यों नहीं जा सकते।

इंडिगो आठ अक्टूबर से मुंबई से कोपेनहेगन की सीधी उड़ान शुरू करेगी

मुंबई

एयरलाइन कंपनी इंडिगो 8 अक्टूबर से मुंबई से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी, जिससे उत्तरी यूरोप में उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का और विस्तार होगा। इंडिगो ने मंगलवार को कहा कि नई सेवाएं सप्ताह में तीन बार संचालित की जाएंगी और इसके लिए वह नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से पट्टे पर लिए गए बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान का इस्तेमाल करेगी। कंपनी के मुताबिक इस मार्ग पर ग्राहकों के पास इकोनॉमी क्लास के साथ-साथ इंडिगो के विशेष व्यावसायिक उत्पाद, इंडिगोस्ट्रेच में उड़ान भरने का विकल्प होगा। वे लगभग 300 घंटे की आकर्षक सामग्री के साथ-साथ उड़ान के दौरान मनोरंजन के साथ-साथ मुफ्त गर्म भोजन और पेय पदार्थों का आनंद ले सकेंगे। इंडिगो ने बताया कि ये उड़ानें अब सभी प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें इंडिगो की वेबसाइट , मोबाइल ऐप और सभी अधिकृत यात्रा साझेदार शामिल हैं। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइन अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का उत्तरी यूरोप में विस्तार करेगी, जिससे कोपेनहेगन उसका 44वां अंतरराष्ट्रीय और कुल मिलाकर 138वां गंतव्य बन जाएगा।

सर्राफा बाजार में सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी की कीमत में आया उछाल

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे दिन सोने के भाव में मामूली गिरावट नजर आ रही है। दूसरी ओर चांदी आज 1,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगा हो गया है। सोने की कीमत में गिरावट आने के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,11,050 रुपये से लेकर 1,11,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 1,01,790 रुपये से लेकर 1,01,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में उछाल आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सराफा बाजार में आज 1,34,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,11,200 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,01,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों को उनके धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली नयी याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन राज्यों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। उच्चतम न्यायालय ने सिटिजंस फॉर जस्टिस की दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश के अलावा मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों की ओर से

बनाया गया कानून विभिन्न धर्मों के जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गया है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून नागरिकों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, इसलिए मांग की गयी है कि मामले की सुनवाई होनेव तक इस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि यूपी धर्मांतरण संशोधन कानून की धाराएं 2 और 3 काफी भ्रमपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये कानून स्वतंत्र अभिव्यक्ति और धार्मिक विश्वास को आघात पहुंचाता है। याचिका में कहा गया है कि यूपी का धर्मांतरण कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 19, 21 और 25 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि यूपी धर्मांतरण संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। इस कानून में प्रशासन की ओर से दुरुपयोग रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी निर्दोष नागरिक को इस मामले में फंसाया जाता है तो उसे रोकने का कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है।

मदर डेयरी ने दूध, पनीर और घी के दाम घटाये, नई कीमतें 22 सितंबर से होंगी लागू

नई दिल्ली

मदर डेयरी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में 100 फीसदी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देगी। इसीलिए अब अपने उत्पादों की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कटौती करने का ऐलान किया है। ये नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। मदर डेयरी ने मंगलवार को रोजमर्रा की जरूरतों वाले उत्पादों जैसे टोन्ड मिल्क, पनीर, बटर, घी, पनीर और प्रीमियम गाय के घी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कीमतों में कटौती के बाद एक लीटर टोंड यूएचटी टेट्रा पैक दूध की कीमत 77 रुपये प्रति लीटर से

घटकर 75 रुपये हो जाएगी, जबकि 450 एमएल वाला पैक अब 33 रुपये के बजाय 32 रुपये में मिलेगा। फ्लेवर्ड मिल्कशेक के 180 एमएल पैक की कीमत भी 30 रुपये से घटकर 28 रुपये हो जाएगी। मदर डेयरी ने पनीर के दामों में भी कटौती की है। अब 200 ग्राम वाला पनीर 95 रुपये की जगह 92 रुपये में और 400 ग्राम वाला पनीर का पैकेट 180 रुपये की जगह 174 रुपये में मिलेगा। इसी तरह मलाई पनीर का 200 ग्राम पैक भी 100 रुपये से घटकर 97 रुपये में बिकेगा। इसी तरह घी और मक्खन के दामों में भी राहत दी गई है। अब 500 ग्राम वाला मक्खन 305 रुपये के बजाय 285 रुपये में और 1 लीटर घी का कार्टन पैक 675 रुपये की बजाय 645 रुपये में मिलेगा। मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंडलिश ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती उपभोक्ताओं के लिए सीधी राहत है। उन्?होंने कहा कि? हम सरकार के जीएसटी के लाभ को बिना किसी देरी के ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। इससे पैक्ड फूड्स की खपत बढ़ेगी, किसानों की आमदनी में सुधार होगा।

भारत के प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्षेत्र में नए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली

भारत के प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग को नई दिशा देने वाले एक अभूतपूर्व कदम के तहत इंडियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड अलाइड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएएमए) और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रिंटर्स एंड पैकेजर्स (एआईएफपीपी) ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित आईपीएएमए कार्यालय में सोमवार को हस्ताक्षरित यह समझौता ज्ञापन इस उद्योग के दो दिग्गजों को एकजुट करने का काम करेगा। इससे देशभर में लगभग 250,000 उद्यमियों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और वैश्विक मान्यता के प्रति नवीन उत्साह बढेगा। यह समझौता आईपीएएमए और एआईएफपीपी को प्रदर्शनियों और आयोजनों के लिए विशेष रणनीतिक साझेदार के रूप में भी स्थापित करता है।

दोनो संगठनों के महासचिवों इकबाल सिंह और सुनील जैन ने इस समझौते को औपचारिक रूप प्रदान किया। इसमें आईपीएएमए अध्यक्ष जयवीर सिंह और एआईएफपीपी के प्रमुख अश्विनी गुप्ता का भी विशेष योगदान रहा। उद्योग जगत के कई प्रतिष्ठित दिग्गज उपस्थित थे जिनमें आर सुरेश कुमार, धरम पाल रावत, शिव कुमार शर्मा, कुलजीत सिंह मान, प्रशांत वत्स, राजेश सरदाना, विजय मोहन, संदीप अग्रवाल, मुकेश कुमार, प्रशांत अग्रवाल, दीपक भाटिया और प्रो. कमल मोहन चोपड़ा शामिल थे। यह महत्वपूर्ण साझेदारी इंट्रापैक इंडिया 2025 प्रदर्शनी में प्रतिष्ठित "पैकेजिंग उत्कृष्टता पुरस्कार" के साथ शुरू होगी जो 10 से 13 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगी। इस दौरान विशेष पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आईपीएएमए आयोजन स्थल, बैठने की व्यवस्था और प्रचार संबंधी सहायता सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा जबकि एआईएफपीपी पुरस्कार ढांचे, प्रविष्टि मूल्यांकन और आयोजन की व्यवस्था का नेतृत्व करेगा। यह सहयोग 2027 में 17वीं प्रिंटपैक इंडिया प्रदर्शनी तक अपनी गतिविधियों में तेजी लाएगा।

बारिश का कहर: मंडी के धर्मपुर में सोनखड्डु में आई बाढ़, बस स्टैंड डूबा, वाहन बहे

मंडी

मंडी जिले में सोमवार बीती रात भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की सोनखड्डु में बारिश के चलते बाढ़ आ गई, आलम यह था कि सोनखड्डु ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। रात 11 बजे से शुरू हुई बारिश रात एक बजे तक इतनी तेज हो गई कि लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। जिसके चलते धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न हो गया। जिसकी वजह से बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी की बसें पानी में डूब

गई। यही नहीं पानी के तेज बहाव में बस अड्डे पर खड़ी एचआरटीसी की कुछ बसें तेज बहाव में बह गई। सोन खड्डु में पानी का भराव इतना भारी था कि बस स्टैंड की एक मंजिल पूरी तरह पानी में समा गई। जिसमें अड्डे में खड़ी एचआरटीसी की बसें भी डूब गई, पानी का भराव इतना था कि बसों का केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इसके अलावा बस अडडे की दुकानों में भी पानी भर गया। इसके अलावा सोनखड्डु के किनारे स्थित घर भी पानी में डूब गए। दर्जनों निजी वाहन जिनमें स्कूटर, बाइक और कारें शामिल हैं पानी के तेज बहाव में बह गईं। मौसम विभाग ने 15 सितंबर से मानसून की गतिविधियों में कमी का पूवार्नुमान जताया था। लेकिन मंडी जिले के सरकाघाट और धर्मपुर उपमंडलों में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई।

केंद्र सरकार ने तेलंगाना और बिहार में सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने तेलंगाना और बिहार में सड़क एवं पुल विकास से जुड़ी 2415.55 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की दो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में 34 सड़क और पुल विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 422.36 किलोमीटर होगी। इन योजनाओं पर 868 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य राज्य की कनेक्टिविटी और परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार सड़क अवसंरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे तेलंगाना में समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-327 ई पर परससमा से अररिया तक 102.193 किलोमीटर लंबे मार्ग को पक्का शोल्डर सहित टू-लेन ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन कार्य के लिए 1547.55 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है।

भारत को अगले 5 साल में बायोफ्यूल और हरित परिवहन में अग्रणी बनाने का लक्ष्य: गडकरी

नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि अगले पांच सालों में भारत को बायोफ्यूल एवं हरित परिवहन में दुनिया में अग्रणी बनाने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के धौलाकुआं से हरियाणा के मानेसर तक हवाई पॉड सिस्टम विकसित करने और मुंबई में जलमार्ग परिवहन के बारे में भी जानकारी दी। गडकरी ने दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली के धौलाकुआं से हरियाणा के मानेसर तक हवाई पॉड सिस्टम विकसित किया जाएगा, जहां बुधवार को पांच वैश्विक कंपनियों के प्रेजेंटेशन होंगे। ये पॉड 18-25 यात्रियों वाले होंगे, जो हवा में 200 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे, हालांकि रुकावटों के कारण गति कम रहेगी। देशभर में 300

केबल कार प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो ट्रैफिक मुक्ति का नया आयाम साबित होंगे। उन्होंने मुंबई के लिए जलमार्गीय परिवहन पर कहा कि उनके प्रयासों से एयरपोर्ट पर जेटी का निर्माण हो चुका है और बीपीटी चेयरमैन के अध्ययन के बाद 5-6 हजार वॉटर टैक्सी चलाने का प्लान है। वेनिस शहर की तर्ज पर ये टैक्सी मुंबईवासियों को समुद्र मार्ग से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक 17 मिनट में पहुंचाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी का चयन कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा के बाद यह राज्य प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह हाल में ही यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया गए थे, वहां से प्रेरित होकर देश में भी फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस किया जा रहा है। देश में जल्दी ही 135 सीटों वाली फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसें जल्द उतारी जाएंगी, जो डीजल बसों से 30 प्रतिशत सस्ती होंगी। इन बसों में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं जैसे आरामदायक सीटें, फ्रंट टीवी स्क्रीन और मोबाइल या कार्ड से एंट्री होगी। उन्होंने कहा कि हर स्टॉप पर मात्र 20-30 सेकंड में चार्ज हो जाने वाली ये बसें नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही हैं। टाटा कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धारवाड़ में इनका निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। उन्होंने मेट्रो की ऊंची लागत (550 करोड़ रुपये प्रति किमी) की तुलना में इन बसों की किफायती कीमत (केवल 2 करोड़ प्रति किमी) का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली से जयपुर जैसे रूट पर ये बसें ढाई घंटे में यात्रा पूरी कर सकेंगी, जिससे मेट्रो जैसी सुविधा सस्ते में उपलब्ध होगी। उन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 450 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि साथ ही डायवर्जन के लिए नए नियम बनाए गए हैं, ताकि अस्थायी समाधानों पर निर्भरता खत्म हो। उन्होंने सड़क हादसों पर कहा कि सरकार इंजीनियरिंग सुधार, फ्लाईओवर निर्माण तथा ब्लैक स्पॉट्स सुधार पर ध्यान दे रही है। कारों में अब चार की जगह छह एयरबैग अनिवार्य हो गए हैं। हालांकि, मुख्य समस्या लोगों की लापरवाही जैसे बिना हेलमेट बाइक चलाना या सिग्नल तोड़ना है।

शिमला में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, प्रदेश में 650 सड़कें बंद

शिमला

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी शिमला में बीती रात कुछ घंटों में 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन की अब तक की सबसे भारी वर्षा है। अचानक हुई इस मूसलाधार बारिश से शहर में जगह-जगह भूस्खलन हुए और सड़कें मलबे से पाट दी गईं। हिमलैंड, कच्चीघाटी और बीसीएस इलाकों में पहाड़ खिसकने और पेड़ गिरने से दस से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। खासकर कार्ट रोड पर हिमलैंड के पास भूस्खलन से पांच से छह वाहन मलबे की चपेट में आ गए और शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली यह सड़क पूरी तरह बंद हो गई। मंगलवार सुबह लोग अपने गंतव्य तक पैदल ही पहुंचे और घंटों जाम का सामना किया। बीसीएस में पेड़ गिरने से तीन-चार वाहन क्षतिग्रस्त हुए जबकि टूटीकंडी और पांजरी में भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसी तरह कनलोग में भी भूस्खलन की घटना सामने आई है प्रशासन के अनुसार कच्चीघाटी और बीसीएस में वन वे ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है जबकि हिमलैंड में युद्ध स्तर पर सड़क बहाली का काम जारी है। बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। शिमला के अलावा कांगड़ा के नगरोटा सूरियाँ में 135 मिलीमीटर, चंबा के चुआड़ी में 80, मंडी के सुंदरनगर में 60, सलापड़ में 57, ब्रह्माणे व गुलेर में 54-54 और मंडी शहर में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

"यह केंद्र महिलाओं को उच्च मानदंडों के हिसाब से इलाज प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम है जो विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर उपचार के लिए समर्पित है"

एशिया के पहले महिला कैंसर सेंटर 'अपोलो एथेना' का शुभारंभ

दिल्ली सरकार आधुनिक हेल्थकेयर संस्थानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में भूमिका निभाएगा: बांसुरी

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राजधानी के डिफेंस कॉलोनी में अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड (एएचईएल) के तहत एशिया के पहले महिला कैंसर अस्पताल "अपोलो एथेना" का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र महिलाओं को उच्च मानदंडों के हिसाब से इलाज प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम है जो विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर उपचार के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, "अपोलो एथेना महिला स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा कदम है। यह एशिया की पहली समर्पित कैंसर उपचार सुविधा है, जिसे अपोलो द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया है। इससे न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश और दुनिया भर की महिलाओं को फायदा होगा।" उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आधुनिक हेल्थकेयर संस्थानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी। गुप्ता ने बताया कि यह केंद्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जहां उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम कैंसर के शुरूआती लक्षणों का पता लगाने से लेकर पूर्ण उपचार तक की सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स की यह पहल महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज और एएचईएल के संस्थापक अध्यक्ष डॉ.प्रताप सी रेड्डी भी मौजूद थे। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह कदम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है जो महिलाओं को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी।

सीएम रेखा ने महिला श्रमिकों संग मनाया विश्वकर्मा पूजा, श्रमिकों से की मन की बात

नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में विश्वकर्मा पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बुधवार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी बीच मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस स्थित वीआर मेट्रोपोलिटन में आयोजित विश्वकर्मा पूजा महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महिला श्रमिकों से मुलाकात कर उनसे उनकी दिनचर्या और काम के बारे में भी बातचीत की। इस संबंध में दिल्ली की सीएम ने इंटनेट मीडिया पर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर संदेश देते हुए लिखा, 'नॉर्थ दिल्ली मेट्रो मॉल में विश?वकर्मा पूजा उत्सव पर विश?वकर्मा भाइयों-बहनों के साथ संवाद का अवसर मिला। आपकी मेहनत और कौशल ही दिल्ली और देश की धड़कन हैं। आप ही कल का भविष्य गढ़ते हैं, आपके श्रम से ही सपनों का भारत खड़ा है। हमारी सरकार आप सभी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे न्यूनतम मजदूरी की बराबरी और बढ़ोतरी हो, पक्का घर का सपना हो, बच्चों का सहारा हो या बीमारी के समय निःशुल्क इलाज की गारंटी, हर कदम आपके जीवन को सुरक्षित और गरिमामय बनाने की दिशा में है।

डेंगू नियंत्रण के मामले में सामुदायिक भूमिका जरुरी: जेपी नड्डा

इस वर्ष डेंगू के मामले 47 प्रतिशत कम और मौतें 73 प्रतिशत कम होने का अनुमान

नई दिल्ली
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में इस वर्ष डेंगू के मामले 2024 के मुकाबले 47 प्रतिशत कम और मौतें 73 प्रतिशत कम होने का अनुमान है। इस दिशा में सामुदायिक प्रयास जरूरी है। नड्डा को दिल्ली एनसीआर में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इसमें देश भर में डेंगू की स्थिति और तैयारियों का ब्यौरा भी शामिल था। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 2024 के दौरान, देश में कुल 2,33,519 डेंगू के मामले और 297 मौतें दर्ज की गईं। 2025 (31 अगस्त तक) में, 49,573 मामले और 42 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली में इस वर्ष 31 अगस्त तक 964 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,215 मामले सामने आए थे। पड़ोसी एनसीआर राज्यों में, उत्तर प्रदेश से 1646, हरियाणा से 298 और राजस्थान से 1181 मामले सामने आए हैं। नड्डा ने डेंगू नियंत्रण के मामले में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्यों से अपनी तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया। साथ ही लंबे समय से जारी बरसात के मौसम और कुछ क्षेत्रों में जलभराव के मद्देनजर जन भागीदारी को बढ़ाने का आग्रह किया।

फर्जी पासपोर्ट-वीजा दिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली
भारत में अवैध रूप से रह रहे अफ्रीकी व दूसरे विदेशी नागरिकों को फर्जी पासपोर्ट-वीजा दिलवाने वाले गिरोह का दक्षिण जिला के स्पेशल स्टाफ ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में चार नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान न्वाचुकु बेंजामिन (33), इमैनुएल इफियानीचुकु (34), पॉल ओलिसामेका (37) और एक महिला प्रीशियस ओसासेरे (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने

आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, कलर प्रिंटर, 3 पैन ड्राइव, 7 मोबाइल फोन, 2 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड, 6 फर्जी पासपोर्ट और वीजा व 17 हजार कैश बरामद किया है।

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में एक गवाह का बयान दर्ज

गवाह और एएसआई रवि दत्त शर्मा का बयान दर्ज किया गया

नई दिल्ली
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आज एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। दूसरे गवाह की तबीयत खराब होने की वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आरोपित स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं। स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकील शिवम मल्होत्रा ने कोर्ट से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। गवाह और एएसआई रवि दत्त शर्मा का बयान दर्ज किया गया। रवि दत्त शर्मा का स्वाति मालीवाल के वकील ने क्रास-एग्जामिनेशन किया। आज सुनवाई के दौरान दूसरे गवाह डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी। कोर्ट ने 25 सितंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह और कांस्टेबल अरुण कुमार के बयान दर्ज करने का आदेश दिया। अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट ने 21 अगस्त को रिटायर्ड एसआई रुप सिंह का बयान दर्ज किया था। 19 अगस्त को दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए थे। 30 जुलाई को मनोज कुमार और उषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया गया था। 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

डूसू का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को हाई कोर्ट की चेतावनी

नियमों और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई-हाईकोर्ट

नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर कल यानि 16 सितंबर को भी सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डूसू के चुनाव में छात्र संगठनों की बड़ी भूमिका है। कोर्ट ने छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों को निर्देश दें कि वो नियमों का पालन करें। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि कोई उल्लंघन या संपत्तियों का विरुपण नहीं किया गया है।

पुलिसकर्मी बनकर आए बदमाशों ने एक करोड़ 40 लाख लूटे

ज्वेलर की कार से 45 लाख की चोरी आकाश नामक बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली
शाहदरा जिले के फर्श बाजार स्थित छोटा बाजार इलाके में दोपहर पुलिसकर्मी बनकर आए बदमाशों ने ज्वेलर के कारखाने से एक करोड़ 40 लाख का सोना और 20 लाख रुपये कैश लूट लिए। आरोपित चेकिंग के बहाने कारखाने में घुसे। बदमाश ने कारखाने में चोरी का सोना गलाने की बात कर कर्मचारियों को पीटा। बाद में वह सोना और कैश लेकर जाते समय थाने आने की बात कर निकल गए। कर्मचारियों ने अपने मालिक को सारी बताई। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फर्श बाजार थाने में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन की जा रही है। शुरूआती जांच के बाद आशंका व्यक्त की जा रही है कि वारदात में ज्वेलर के किसी करीबी का हाथ हो सकता है।

युवक की चाकू घोंपकर हत्या

नई दिल्ली
प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवक ने अपनी बहन के प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना भजनपुरा के सुभाष विहार इलाके की है। मृतक की पहचान अभिषेक शर्मा उर्फ तन्नू (28) के रूप में हुई है। सुबह आरोपित ने अपने घर के पास वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि अभिषेक सुभाष विहार की एक युवती से प्यार करता था। दोनों अक्सर मिलते थे। इस बात का लड़की का भाई ऐतराज करता था। रविवार रात को भी आरोपित का अभिषेक से झगड़ा हुआ था। पुलिस आशंका जता रही है कि इसी वजह से हत्या की गई। जिले के पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

आरोपित की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की सही वजहों का खुलासा हो पाएगा। वहीं अभिषेक के परिजन प्रेम प्रसंग की बात से इंकार कर रहे हैं।

पुलिस ने भगोड़े बदमाश को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और हरियाणा के कई मामलों में फरार चल रहे एक भगोड़े ग्रेजुएट बदमाश को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपित की पहचान बागपत निवासी रजत तोमर उर्फ राजबीर (45) के रूप में हुई है। आरोपित पिछले करीब पांच सालों से पुलिस की टीम को चकमा देकर रह रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना नाम रजत से बदलकर राजबीर कर लिया था।

डूसू चुनाव को लेकर कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक

नई दिल्ली
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2025-26 के सुचारू और निष्पक्ष संचालन को लेकर कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में को विश्वविद्यालय प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीन ऑफ कॉलेज प्रो. बलराम पाणी, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता, प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा, मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. राजेश सिंह, डीसीपी (उत्तरी जिला) राजा बंथा, दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रोवोस्ट और छात्रावास वार्डन उपस्थित रहे। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि डूसू चुनाव में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हत्या के मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में शादी से इंकार करने पर प्रेमिका की हत्या करने के मामले में आठ साल से फरार चल रहे एक लाख के इनामी बदमाश को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान बिहार निवासी अर्जुन कुमार उर्फ भोला (31) के रूप में हुई है। प्रेमिका की हत्या करने के बाद आरोपित नेपाल भाग गया था। वहां उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक महिला की हत्या कर दी।

दिल्ली डेंटल काउंसिल मौलाना आजाद दंत चिकित्सा संस्थान में हुआ शिफ्ट

दंत चिकित्सकों, डेंटल और डेंटल मैकेनिक्स को पंजीकृत करना है

नई दिल्ली
दांतों के डॉक्टरों के पंजीकरण से लेकर पेशा नियमों और मानकों के साथ दंत चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने वाली दिल्ली डेंटल काउंसिल (डीडीसी) के कार्यालय का स्थानांतरण हो गया है। अब डीडीसी के पदाधिकारी मेटकॉफ हाउस या विकास भवन की जगह मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एमएआईडीएस) के भवन परिसर में बैठेंगे। डीडीसी के प्रभारी रजिस्ट्रार डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दंत चिकित्सकों की सुविधा के लिए डीडीसी का दफ्तर एमएआईडीएस में स्थानांतरित कर दिया है। इसके लिए अस्पताल के मुख्य भवन का सातवां तल नए सिरे से विकसित किया गया है। इसमें चेयरमैन सहित तमाम संवैधानिक पदाधिकारियों के कार्यालय बनाए गए हैं जो डीडीसी में पंजीकृत करीब 2200 दंत चिकित्सकों की नीतिगत समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉ. ज्ञानेंद्र के मुताबिक दिल्ली डेंटल काउंसिल का मुख्य काम दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के तहत दिल्ली में दंत चिकित्सकों, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स को पंजीकृत करना है।

एमसीडी शिक्षा विभाग के निदेशक संजय सिंह का तबादला: विपक्ष ने उठाए सवाल

सीनियरिटी लिस्ट और लिस्ट में हुई कथित धांधलियों की निष्पक्ष जांच होगी

नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता प्रतिपक्ष अंश नारंग ने शिक्षा विभाग के निदेशक संजय सिंह का अचानक तबादला होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कदम विभाग में चल रही अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई व्यवस्था में सीनियरिटी लिस्ट और प्रिंसिपल प्रमोशन लिस्ट में हुई कथित धांधलियों की निष्पक्ष जांच होगी। अंकुश नारंग ने बताया कि एमसीडी शिक्षा विभाग में सीनियरिटी लिस्ट, प्रिंसिपल प्रमोशन लिस्ट और शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को आआपा ने लंबे समय से उठाया है। इन मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए संजय सिंह को शिक्षा निदेशक पद से हटा दिया गया। नारंग ने कहा कि अब निगमायुक्त को इन अनियमितताओं की जांच करानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नारंग ने 30 जून 2025 को आयोजित पत्रकार वार्ता का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग की वरिष्ठता सूची (1995 से 2002 तक) और स्थानांतरण नीति में गड़बड़ियां उजागर की गई थीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (डीएसएसबी) ने 2001 में पहली भर्ती की थी, लेकिन विभाग ने बिना उचित मापदंडों के मेरिट लिस्ट तैयार कर ली। प्रमोशन सूची में मार्क्स को खाली छोड़ दिया गया और केवल सेवानिवृत्ति की तारीख (30 जून 2025) दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठता सूची सही नहीं थी, तो प्रमोशन कैसे सही हो सकती है? नारंग ने कहा कि शिक्षा निदेशक का तबादला तुरंत प्रभाव से हुआ है, जो विभाग में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि निगम आयुक्त इन मुद्दों की गहन जांच कराएं और प्रभावित शिक्षकों को न्याय मिले। एमसीडी शिक्षा विभाग के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की शिक्षा पर इन अनियमितताओं का असर पड़ रहा है।

डीयू के कॉलेजों में बौद्ध व आंबेडकर अध्ययन सेंटर खोलने की मांग

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखा

नई दिल्ली
फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखकर राजधानी के सभी 28 वित्त पोषित कॉलेजों में बौद्ध अध्ययन विभाग और डॉ. आम्बेडकर अध्ययन सेंटर स्थापित करने की मांग की। इन विभागों के खुलने से छात्रों और शिक्षकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत का बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। बौद्ध अध्ययन में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं और इस विषय से जुड़े छात्र शिक्षा, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास और साहित्य जैसे क्षेत्रों में शोध और अध्यापन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जय भीम योजना चलाई गई थी, वैसे ही उच्च शिक्षा में भी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं।

संपादकीय

वोटर अधिकार यात्रा ने उजागर किया विपक्ष का बिखरा चेहरा

राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में चली ह्यवोटर अधिकार यात्राह्न 1 सितंबर को पटना में समाप्त हो चुकी है। यह यात्रा 17 अगस्त को रोहतास जिले से शुरू हुई थी और करीब दो हफ्तों तक बिहार के अलग-अलग जिलों से गुजरते हुए विपक्षी राजनीति को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास करती रही। इस यात्रा का मकसद न केवल ह्यवोट चोरीह्न जैसे आरोपों को प्रमुखता से उठाना था, बल्कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता और मतदाता सूची में चल रहे एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की प्रक्रिया को भी विपक्ष की केंद्रीय बहस का मुद्दा बनाना था।

यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें कांग्रेस के साथ-साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव और वाम दलों के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी लगातार शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मौजूदगी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन राजनीति के इस मंच से ममता बनर्जी की अनुपस्थिति ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस यात्रा से दूर रहीं। यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक भी थी। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर अपने दो सांसद यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी को पटना भेजा, लेकिन यह स्पष्ट था कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी की इस पहल से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहता है।

जानकार कहते हैं कि ममता बनर्जी का रवैया समझना आसान नहीं है। वे चाहतीं तो खुद इस यात्रा का हिस्सा बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाए रखी। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें कांग्रेस के साथ खड़े होने से अपने ही राज्य में राजनीतिक जोखिम दिखता है। दरअसल, पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव बेहद अहम हैं। 2021 में भारी जीत के बावजूद ममता बनर्जी के सामने एंटी-इनकंबेंसी, बीजेपी का दबाव, और कांग्रेस-लेफ्ट के साथ स्थानीय स्तर पर सीधी टक्कर जैसी कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करना ममता के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता था।

बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं, और यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ होगा।राहुल गांधी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनावों में व्यापक स्तर पर वोट चोरी हुई है। यही आरोप उनका राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है। आरजेडी और वामपंथी दलों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने भी एसआईआर पर आक्रामक रुख अपनाया है। ममता ने कहा है कि अगर एक भी असली वोटर का नाम काटा गया तो वे 10 लाख कार्यकताओं के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव करेंगी।

यानी मुद्दा वही वोटरों के अधिकार की रक्षा से जुड़ा है, लेकिन जब बात राहुल गांधी की यात्रा की आई तो ममता ने दूरी बनाए रखी। यह दूरी विपक्षी एकता की संभावनाओं पर कई सवाल खड़े करती है। पश्चिम बंगाल और बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी लगभग 27 फीसदी है। ममता बनर्जी के पास लंबे समय से यह वोट बैंक मजबूती से रहा है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में मुस्लिमों की बड़ी भागीदारी देखी गई। जगह-जगह मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस और आरजेडी के कार्यक्रमों में नजर आए। यह ममता के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उन्हें आशंका है कि राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति अगर मुस्लिम वोटरों पर असर डालने लगी तो इसका असर बंगाल तक पहुंच सकता है। याद रखना होगा कि 2021 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस और वामदलों ने मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी का यह नया अभियान भविष्य में समीकरण बदल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की कमान भले ही साझा हो, लेकिन असली चेहरा तेजस्वी यादव का है। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और कांग्रेस-लेफ्ट ने भी कुछ सीटें जीती थीं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर, बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा, लेकिन हार होने पर इसका ठीकरा राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी फोड़ा जाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस यात्रा से दूर रहीं, क्योंकि हार की सूरत में उनके ऊपर भी राजनीतिक दाग लग सकता था।यानी ममता का निर्णय महज रणनीतिक नहीं बल्कि जोखिम प्रबंधन भी है। वे चाहती हैं कि बिहार की राजनीति में उनके नाम का न जुड़ना ही उनके लिए सुरक्षित रहेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन की एकता पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं।

टीएमसी और कांग्रेस के बीच तकरार लोकसभा चुनावों में भी साफ दिखाई दी थी। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में, राहुल गांधी की यात्रा विपक्ष को एकजुट करने का मंच बन सकती थी, लेकिन ममता और केजरीवाल की गैरमौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन अब भी ढीला-ढाला समझौता ही है। यात्रा में अखिलेश यादव और स्टालिन की मौजूदगी ने कांग्रेस को साउथ और यूपी से समर्थन का संदेश दिया, लेकिन बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों से दूरी ने यह दिखाया कि विपक्ष के भीतर क्षेत्रीय दल अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कदम उठा रहे हैं। ममता की दूरी की एक ऐतिहासिक वजह भी है। पश्चिम बंगाल और बिहार की राजनीति का रिश्ता कभी बहुत मधुर नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव से ममता का पुराना मतभेद किसी से छिपा नहीं है। रेल मंत्री रहते हुए दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सार्वजनिक विवाद हुए थे।इस पृष्ठभूमि में ममता का बिहार की राजनीति से दूरी बनाना कोई नई बात नहीं है। वे अपने राज्य के मुद्दों पर ही फोकस करना चाहती हैं और राष्ट्रीय राजनीति में केवल उतना ही निवेश करती हैं, जितना उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद हो। ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता में हैं। लंबे शासन का एक असर यह भी है कि राज्य में एंटी-इनकंबेंसी का माहौल धीरे-धीरे गहराने लगता है। भ्रष्टाचार, घोटाले, और बेरोजगारी जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए हथियार बने हुए हैं। इस स्थिति में अगर ममता कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा निकटता दिखातीं तो यह संदेश जाता कि वे विपक्षी गठबंधन पर निर्भर हैं, जबकि बंगाल में वे अभी भी अपनी मजबूत एकल पहचान बनाए रखना चाहती हैं। यही कारण है कि उन्होंने यात्रा से दूरी बनाई और केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भेजा।भले ही ममता बनर्जी और केजरीवाल ने दूरी बनाई हो, लेकिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस को नया ऊर्जा स्रोत दिया है। कांग्रेस के झंडे, राहुल गांधी के नारे और जनता की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि पार्टी अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यह यात्रा राहुल गांधी के लिए भी एक नेतृत्व परीक्षण थी। वे दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस केवल चुनावी गठबंधन का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने वाली पार्टी भी है।

कुल मिलाकर, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन की सीमाओं को भी उजागर कर दिया है। ममता बनर्जी का इसमें शामिल न होना यह दशार्ता है कि भारत की विपक्षी राजनीति अभी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, क्षेत्रीय हितों और राजनीतिक जोखिमों के बीच उलझी हुई है। ममता की रणनीति साफ है कि वे बंगाल पर केंद्रित रहना चाहती हैं, कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहती हैं और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहतीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के अनुरूप शासन के लिए कर्मचारी से कर्मयोगी तक का खाका किया तैयार

देश लोक प्रशासन में सुधार के अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। अब न केवल अधिकारियों के प्रशिक्षण के तरीके बदल रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा के मायनों में भी बदलाव आ रहा है। मिशन कर्मयोगी–लोक सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस बदलाव में इंजन की भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच झलकती है। 25 वर्षों से अधिक समय तक सरकार चलाने और पांच दशकों से अधिक सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले मोदी, व्यवस्थाओं के प्रति एक संचालक जैसी समझ, जड़ आदतों के प्रति एक सुधारक जैसी अधीरता, और ध्रुव तारे की तरह स्पष्ट – नागरिक-प्रथम, विकसित भारत के उद्देश्य को सामने रखते हैं।

मिशन कर्मयोगी की खासियत यह है कि यह केवल दिखावे भर के लिये मानव संसाधन सुधार नहीं है। यह देश की लोक सेवाओं की मूल्य-आधारित परिवर्तनकारी पुनर्रचना है और इसका मुख्य ध्यान प्रदर्शन पर है। यह कार्यक्रम तीन निर्णायक बदलावों को संहिताबद्ध करता है:

पहला बदलाव सरकारी अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव है, यानी स्वयं को कर्मचारी मानने से लेकर कर्मयोगी मानने तक का सफर है।

दूसरा बदलाव कार्यस्थल में बदलाव है, इसमें प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी सौंपने से लेकर प्रणालीगत प्रदर्शन बाधाओं का निदान और उन्हें दूर करने तक का बदलाव शामिल है।

तीसरा बदलाव सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और उससे जुड़ी क्षमता निर्माण प्रणाली को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है। यह संरचना स्पष्ट रूप से मोदी के इक्कीसवीं सदी के शासन की मांगों के दूरदर्शी ढांचे से उभर कर सामने आयी है।

यह जीवंत नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी ने एक समग्र सरकारी संस्कृति को बढ़ावा दिया– अलग-अलग क्षेत्रों में अलगाव को खत्म किया, मंत्रियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बहस पर बल दिया, और फाइलों को आगे बढ़ाने की बजाय सिस्टम समाधानों को प्राथमिकता दी। यह भावना महामारी के दौरान दिखाई दी, जब सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और नागरिक स्वयंसेवकों के सभी स्तरों पर टीम इंडिया एक साझेदारी मॉडल के रूप में आगे बढ़ी। यही सहयोगात्मक शक्ति अब जीईएम और गतिशक्ति जैसे सुधारों को संस्थागत रूप दे रही है।

उन्होंने नेतृत्व की आदतों को संरचनाओं में भी ढाला। जो चिंतन शिविर–आवासीय, पदानुक्रम-समतल विचार-मंथन सत्र– गुजरात में शुरू किए गए थे वे अब केंद्र सरकार की कार्यपुस्तिका का हिस्सा हैं। निरंतर सीखने पर उनका बल व्यक्तिगत है। अपने ज्ञान और कौशल का निरंतर विस्तार करने के अलावा, वे यह भी जांचने के लिए जाने जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी आईजीओटी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। संस्थागत स्मृति के साथ उनके व्यवहार में बहुत समावेशीता है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने मंत्रियों से दशकों तक एक तरह से व्यवस्था से भली-भांति परिचित अपने सहायकों और अनुभाग अधिकारियों से सीखने का आग्रह किया। व्यवहार में संस्कृति परिवर्तन ऐसा ही दिखाई देता है। जमीनी स्तर पर, सुधार की रीढ़ उद्देश्यपूर्ण तकनीक है।

आईजीओटी -कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक, कभी भी और कहीं भी सीखने का ईको सिस्टम है। इसमें 3,000 से ज्यादा स्व-प्रगति पाठ्यक्रम हैं जो सभी के लिए सुलभ हैं और सीखने को लोकतंत्रात्मक बनाते हैं। यह सीखने को मानव संसाधन कार्यों जैसे योग्यता मानचित्रण, करियर नियोजन और मार्गदर्शन से जोड़ता है–देश को प्रदर्शन पुलिसिंग से सक्षम क्षमता की ओर ले जाता है। यह पहले से ही बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदान कर रहा है। लाखों अधिकारियों को नए कानूनी ढांचों के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है; देश भर में लाखों पुलिस, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी नागरिक संपर्क को मजबूत कर रहे हैं और सेवाभाव कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं; और बड़ी संख्या में लोग एआई और आईओटी जैसी उभरती तकनीकों में प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री की तकनीक-अनुकूल प्राथमिकता संस्थागत ताकत में परिवर्तित हो चुकी है। दार्शनिक सार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिशन कर्मयोगी प्राचीन सभ्यतागत ज्ञान को आधुनिक शासन-कला के साथ जोड़ता है–विकास, गर्व, कर्तव्य और एकता जैसे संकल्पों के साथ-साथ स्वाध्याय, सहकार्यता, राजकर्म और स्वधर्म (नागरिकों पर ध्यान) जैसे व्यक्तिगत गुणों को भी समाहित करता है। यह कोई पुरानी यादें नहीं हैं; यह उच्च तकनीक युग के लिए एक व्यावहारिक नैतिकता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि योग्यता चरित्र में समाहित हो।

नागरिक-केंद्रितता–जनभागीदारी–दूसरा स्तंभ है। प्रधानमंत्री मोदी बार-बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि प्रत्येक सार्वजनिक निर्णय के केंद्र में नागरिक होने चाहिए। यही उनका शासन मंत्र है। व्यवहार में नागरिक सहभागिता दोतरफा समझौता बन जाती है। नीति और क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी होती है और अधिकारी अंतिम छोर पर खड़े अंतिम नागरिक की सेवा के लिए तैयार होते हैं। मिशन कर्मयोगी इस समझौते के लिए मानसिकता और तरीके विकसित करने का राज्य का साधन है।

आत्मनिर्भरता इसकी पूरक है। यह एकाकीपन नहीं है; यह खुलेपन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित क्षमता और आत्मविश्वास है।

यही दृष्टिकोण क्षमता निर्माण के प्रयासों और माईगव जैसे प्लेटफॉर्म के व्यापक प्रसार में भी दिखाई देता है, जो नागरिकों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सह-निमार्ता बनाता है। यह कथा भारत के सभ्यतागत लोकाचार में निहित है–और संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में फलने-फूलने के लिए तैयार करती है।

कार्यक्रम की संस्थागत संरचना प्रधानमंत्री मोदी की व्यावहारिकता को दशार्ती है। डिजिटल आधार और बाजार को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, कर्मयोगी भारत, समन्वय के लिए एक मंत्रीमंडल सचिवालय इकाई; संरक्षक और मानक-निर्धारक के रूप में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी); और शीर्ष-स्तरीय संचालन के लिए प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन परिषद का नेतृत्व किया । इसकी संरचना सहयोगात्मक, लेखा-परीक्षण योग्य और परिणाम-उन्मुख है–एक ऐसा शासन ढांचा जो कहीं से भी काम करने वाले देश के लिए उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो सीखता है उसे संचित नहीं कर रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप, देश अपने ज्ञान, अनुभव और उपकरणों को साझा करने की तैयारी कर रहा है। इन्हें लोक प्रशासन में एक आदर्श के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण है, वहां तकनीकी व्यवधानों के बीच देशों को समान क्षमता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मॉरीशस को इस दिशा में पहले ही सहायता की पेशकश की जा चुकी है–यह एक प्रारंभिक संकेत है कि मिशन कर्मयोगी विकासशील लोकतंत्रों में एक अभ्यास समुदाय का निर्माण कर सकता है।

सीधे शब्दों में कहें तो, मिशन कर्मयोगी एक दूरदर्शी विचार को एक व्यवस्था में बदल देता है। यह प्रधानमंत्री मोदी के शासन के लंबे दायरे–उनकी सीमाओं को तोड़ने की सहज प्रवृत्ति, तकनीक के साथ उनका सहज व्यवहार, संस्थागत स्मृति के प्रति उनके सम्मान और उनकी नैतिक शब्दावली–को एक दोहराए जाने योग्य संचालन मॉडल में बदल देता है: भूमिका-आधारित मानव संसाधन; निरंतर, डिजिटल शिक्षा; नागरिक भागीदारी; और सभ्यता पर आधारित नैतिकता इसमें समाहित हैं। इस तरह आप किसी देश को भविष्य के लिए तैयार करते हैं।

अगर भारत इसी राह पर चलता रहा, तो इसका फायदा सिर्फ. तेज गति से आगे बढने वाली काम की फाइलों और व्यवस्थित संगठनात्मक चार्ट में ही नहीं, बल्कि भरोसे में भी दिखेगा। नागरिक एक ऐसी सरकार का अनुभव करेंगे जो सुनती है, सीखती है और काम करती है। यही प्रधानमंत्री मोदी के दांव का मूल है।

मोदी का शासनः गुजरात मॉडल से भारतीय मॉडल तक

लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने वाले बहुत ही कम नेताओं ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का दायित्व भी संभाला है। देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री ह्यराष्ट्रीयह्न स्तर के नेता रहे हैं और उनके पास संघीय स्तर पर काम करने का अनुभव बहुत ही कम रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इसके चंद अपवादों में से एक हैं।

जब श्री नरेन्द्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो वे अपने साथ गुजरात में एक दशक के राज्य-स्तरीय शासन से विकसित हुए कामकाज के एक नए दर्शन को लेकर आए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इस बात को बारीकी से देखा कि योजनाएं अंतिम छोर पर क्यों विफल या सफल होती हैं और फिर एक ऐसे दृष्टिकोण को परिष्कृत किया जिसने उन्हें शासन के केन्द्र में महज नीति-निर्माण के बजाय क्रियान्वयन को रखने वाला पहला प्रधानमंत्री बनाया। बिजली से लेकर बैंकिंग और कल्याण से लेकर बुनियादी ढांचे के मामले में, इस दर्शन ने तब से आज तक भारतीय राज्य द्वारा अपने नागरिकों की सेवा करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है।

अनुभव के आधार पर विकसित क्रियान्वयन

नीतिगत केन्द्रबिंदु के रूप में क्रियान्वयन में श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ विश्वास को, बिजली क्षेत्र से संबंधित उनके दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। गुजरात में, उन्होंने देखा कि गांवों में खंभे और लाइनें तो हैं, लेकिन वास्तव में बिजली नदारद है। इसका समाधान उन्होंने ज्योतिग्राम योजना के रूप में निकाला, जिसके तहत फीडरों को अलग किया गया ताकि घरों को 24 घंटे बिजली मिल सके और खेतों को बिजली का एक निश्चित हिस्सा मिल सके। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस योजना के जरिए 18,374 गांवों को भरोसेमंद तरीके से बिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023 तक आते - आते, बिजली की यही आपूर्ति सामूहिक रूप से 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करने वाले देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की रीढ़ बन गई।

बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी सिद्धांत को फिर से दोहराया गया। कागजों में तो ग्रामीण परिवारों के बैंक में खाते थे, लेकिन व्यवहार में वे निष्क्रिय थे।

जन-धन ने इस स्थिति को बदल दिया। आधार और मोबाइल फोन को व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़कर, एक कमजोर पड़ी व्यवस्था को सीधे धन हस्तांतरण की बुनियाद बना दिया गया। इससे धन बिना किसी बिचौलिए के नागरिकों के हाथों में पहुंचा, बबार्दी पर लगाम लगी और सरकारी खजाने को भारी रकम की बचत हुई।

इसके बाद आवास क्षेत्र की बारी आई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने भुगतान को निर्माण कार्यों से जोड़ा, उनकी निगरानी के लिए जियो-टैगिंग का इस्तेमाल किया और बेहतर डिजाइन पर जोर दिया। पिछली सरकारों के अधूरे घरों के उद्घाटन के चलन को पलटते हुए, पहली बार लाभार्थियों को पूरी तरह निर्मित और रहने लायक घर मिले।

फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में संघीय प्रणाली

गुजरात ने श्री नरेन्द्र मोदी को यह भी दिखाया कि प्रगति किस प्रकार केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का दर्शन बन गया।

दशकों से अटके पड़े वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को राज्यों के साथ आम सहमति बनाकर पारित किया गया। जीएसटी परिषद ने राजकोषीय संवाद को संस्थागत रूप दिया और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया।

इसके अलावा, उन्होंने राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले केन्द्रीय करों का हिस्सा बढ़ाया। इससे राज्यों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में ज्यादा वित्तीय गुंजाइश एवं स्वायत्तता मिली। साथ ही, उन्होंने व्यापार में सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करके और सुधारों को पुरस्कृत करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया। इन बदलावों ने राज्यों को न सिर्फ धन प्राप्त करने वाले के रूप में, बल्कि भारत की विकास गाथा में हितधारक के रूप में भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बुनियादी ढांचे के मामले में, गुजरात के बीआईएसएजी मानचित्रण से संबंधित प्रयोगों को पीएम गति शक्ति के रूप में विस्तारित किया गया, जहां 16 मंत्रालय और सभी राज्य अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1,400 परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं। इससे अनुमोदन में लगने वाले समय में कमी आ रही है और क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित हो रहा है।

उत्पादकता के रूप में कल्याण

श्री नरेन्द्र मोदी के लिए, कल्याणकारी योजनाएं हमेशा उत्पादकता से जुड़ा निवेश रही हैं जिनका उद्देश्य इनके लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। गुजरात के कन्या केलवणी नामांकन अभियान ने महिला साक्षरता को 2001 के 57.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2011 तक 70.7 प्रतिशत कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर, इसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। इस कार्यक्रम का संबंध बाल लिंगानुपात में सुधार से है, जो 2014 के 918 से बढ़कर 2023 तक 934 हो गया। लड़कियों के स्कूल जाने से उनकी शादी देर से होती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ती है। इससे वे वेतनभोगी कार्यबल में प्रवेश कर सकी हैं और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले रही हैं।

मातृ स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखा गया। गुजरात की चिरंजीवी योजना ने संस्थागत प्रसवों पर सब्सिडी दी, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। केन्द्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने मातृत्व लाभ और पोषण को जोड़ा। इससे तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता मिली। इसका मार्गदर्शक विचार एक ही थाः सामाजिक व्यय से निर्बलता में कमी आनी चाहिए, विकल्प बढ़ने चाहिए और भावी कार्यबल की क्षमता बढ़नी चाहिए।

निवेशकों और नागरिकों का विश्वास

शायद, गुजरात मॉडल का सबसे सूक्ष्म प्रभाव मानसिकता में बदलाव है। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनों ने दिखाया कि कैसे निरंतर जुड़ाव धारणाओं को बदल सकता है, एक राज्य को निवेशकों की नजर में एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य बना सकता है और नौकरशाहों को व्यवसाय के अनुकूल बना सकता है।

इसी अनुभव ने ह्यमेक इन इंडियाह्न को आकार दिया, जिसने सुव्यवस्थित मंजूरियों, भूमि गलियारों और बुनियादी ढांचे की तैयारी के जरिए विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी।

वर्ष 2014 और 2024 के बीच, भारत ने 83 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया, जो इसकी कार्यान्वयन क्षमता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता में भरोसे का संकेत देता है।

नागरिकों के स्तर पर भी उम्मीदें बदल गईं। पहले, योजनाओं का मूल्यांकन घोषणाओं से होता था। आज, आम भारतीय यह मानकर चलते हैं कि सरकार द्वारा समर्थित बिजली, शौचालय, बैंक खाते, सब्सिडी वाली गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं वास्तव में उन तक पहुंचेंगी।

इस तरह की चुपचाप की गई सेवाओं की आपूर्ति और सुविधाओं के सामान्यीकरण ने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया है जहां वादों को उनके क्रियान्वयन से मापा जाता है, न कि उनके इरादों से।

कई मायनों में, यह बढ़ी हुई उम्मीद गुजरात मॉडल की सबसे ठोस विरासत है।

विकसित भारत 2047 की ओर

ह्यसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयासह्न महज एक नारा भर नहीं है। इसकी छाप रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देती हैः बिजली अब लक्जरी नहीं रही, कल्याण सीधे तौर पर उपलब्ध हो रहा है, बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं डिजिटल समन्वय से बनाईं जा रही हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा दिखावे के बजाय मापने योग्य नतीजों की दृष्टि से डिजाइन की गई है। यह अब एक ऐसा भारतीय मॉडल है जिसने शासन को अंतिम छोर तक पहुंचाया है और देश के कोने - कोने में जनजीवन को प्रभावित किया है।

वंशवाद में सिमटती देश की राजनीति

संजय सक्सेना

भारतीय राजनीति में वंशवाद का मुद्दा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एलईडब्लूय) द्वारा 12 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट ने इस पुरानी समस्या को एक बार फिर ताजा कर दिया है। इस रिपोर्ट में देशभर के 5,204 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की गहन पड़ताल की गई और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि हर पांच में से एक नेता, यानी लगभग 21 प्रतिशत जनप्रतिनिधि, राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की कमजोर होती नींव का प्रतीक है। लोकसभा में यह आंकड़ा और भी अधिक, 31 प्रतिशत तक पहुँच गया है। राज्यसभा में 21 प्रतिशत, राज्य विधानसभाओं में 20 प्रतिशत और विधान परिषदों में 22 प्रतिशत नेता परिवारवाद की छाया में राजनीति कर रहे हैं।परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है जिनके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार, राष्ट्रीय जनता दल में लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव,समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, तमिलनाडु में करुणानिधि की वंशवाद वाली सियासत, महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे,रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को,पंजाब में बादल परिवार,हरियाणा में चौटाला परिवार तो बसपा में मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश, पश्मिच बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही उत्तराधिकारी की कुर्सी क्यों मिलती है। क्या पार्टी में परिवार से बाहर के नेताओं की कमी रहती है। बात राष्ट्रीय दलों से शुरू की जाये तो इसमें कांग्रेस सबसे आगे है। नेहरू-गांधी परिवार की विरासत यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नाम सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में वंशवाद का प्रतीक बन चुके हैं। कांग्रेस के कुल नेताओं में 32 प्रतिशत परिवारवादी हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत, भाजपा में 17 प्रतिशत और वामपंथी दल सीपीआई(एम) में केवल 8 प्रतिशत है। इसके विपरीत, तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके जैसी दलों में यह प्रतिशत काफी कम है द्द 10 और 4 प्रतिशत। इसका कारण है कि ये दल मजबूत संगठन और काडर-आधारित संरचना पर विश्वास करते हैं, जिससे नए नेताओं को मौका मिल पाता है।

क्षेत्रीय दलों की स्थिति और भी चिंताजनक है। एनसीपी (शरद पवार गुट) और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 42-42 प्रतिशत नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। वाईएसआर कांग्रेस में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में 36 प्रतिशत है। यह दशार्ता है कि दक्षिण भारत में भी परिवारवाद अब राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुका है।

टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसी के जगन मोहन रेड्डी इसके जीते-जागते उदाहरण हैं।

राज्यवार आंकड़े भी चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश वंशवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। 604 जनप्रतिनिधियों में 141 (23 प्रतिशत) परिवारवादी हैं।

लोकसभा में यूपी के 28 सांसदों में राहुल गांधी (रायबरेली), अखिलेश यादव (कन्नौज), अनुप्रिया पटेल (अपना दल), जितिन प्रसाद (पीलीभीत) और जयंत चौधरी (रालोद) शामिल हैं। राज्यसभा में रामगोपाल यादव, आरपीएन सिंह और नीरज शेखर जैसे नामों ने यह साबित किया कि यहां वंशवाद गहराई तक फैला हुआ है। समाजवादी पार्टी के 161 नेताओं में 48 (30 प्रतिशत) और भाजपा के 17 प्रतिशत नेता वंशवादी हैं।

अनुपात में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 255 नेताओं में 86 (34 प्रतिशत) परिवारवादी हैं।

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले काली मंदिर पर धावा, मूर्तियां तोड़ीं

एजेंसी

ढाका (बांग्लादेश)। बांग्लादेश में नवरात्रि और दुर्गा पूजा से पहले एक हिन्दू मंदिर पर की गई तोड़फोड़ से अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत है। बताया गया है कि रविवार रात कुश्तिया के मीरपुर उप जिला स्थित स्वरूपदाह पालपारा श्री श्री रक्खा काली मंदिर में बदमाशों ने दो मूर्तियों को खंडित कर दिया। बदमाश तोड़फोड़ करने के बाद एक सीसीटीवी और एक मेमोरी कार्ड अपने साथ ले गए। द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मीरपुर थाना प्रभारी मोमिनुल इस्लाम ने बताया कि घटना रविवार रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई होगी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही कोई शिकायत दर्ज की गई है। घटना की जांच की जा रही है। मंदिर समिति के पूर्व सचिव बादल कुमार डे ने कहा कि हम लोग पिछले तीन साल से यहां दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले हुई इस घटना से सभी लोग दहशत में। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने मंदिर का सुरक्षा कैमरा और उसका मेमोरी कार्ड लूट लिया। कुश्तिया के उपायुक्त अबू हसनत मोहम्मद अराफिन ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में मौजूदा सुरक्षा उपायों के बारे में पूछे जाने पर अराफिन ने कहा कि नए कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा, अंसार के सदस्य चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं।

गाजा युद्ध पर विवाद : स्पेन के प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय खेलों से इजराइल को प्रतिबंधित करने की मांग की

मैड्रिड। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने कहा है कि गाजा युद्ध के चलते इजराइल को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बयान तब दिया जब फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने स्पेन की सबसे बड़ी साइकिल रेस वुएल्टा ए एस्पान्या (Vuelta a España) का अंतिम चरण बाधित कर दिया। सांचेज ने 14 सितंबर को हुई इस घटना पर प्रदर्शनकारियों की 'गहरी प्रशंसा' व्यक्त की और कहा कि इजराइल पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी रूस पर यूक्रेन पर हमले के बाद की गई थी। उन्होंने कहा कि 'हमारी स्थिति स्पष्ट है - जब तक यह बर्बरता जारी है, रूस और इजराइल दोनों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए।' करीब एक लाख प्रदर्शनकारी मैड्रिड में जुटे और साइकिल रेस के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने शुरुआत में रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर कब्ज़ा करने दिया। विरोध प्रदर्शन का मुख्य निशाना इजराइल-प्रीमियर टेक टीम रही, जो इस प्रतिष्ठित रेस में शामिल थी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन साआर ने सांचेज पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाते हुए उनकी सरकार को 'स्पेन की शर्म' बताया। स्पेन की विपक्षी पॉपुलर पार्टी ने भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया और कहा कि यह 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी' है।

नेपाल में राष्ट्रीय संकट के बीच रामेश्वर खनाल ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला

काठमांडू। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शनों के दौरान केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। अनुभवी अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री के रूप में, कुलमन घिसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में और वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। खनाल ने देश की आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज ही अपना कार्यभार संभाल लिया है। पिछले साल ही ओली सरकार ने खनाल को आर्थिक सुधार पर एक उच्च स्तरीय आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, जिसकी सिफारिशों का विश्लेषकों और व्यापारिक समुदाय ने व्यापक रूप से स्वागत किया था। खनाल ने बाद में सरकार के साथ नीतिगत असहमति के बाद इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी नियुक्ति इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेन-जी आंदोलन ने सरकारी और निजी संपत्ति को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है।

कतर शिखर सम्मेलन के बीच इजराइल की चेतावनी, हमास नेताओं को कहीं भी निशाना बनाएंगे

दोहा/यरुशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह हमास नेताओं पर हमले की कार्रवाई जहां भी वे हों करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब अरब और इस्लामी देशों के प्रमुख कतर में शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य पिछले सप्ताह कतर पर इजराइल के हमले के बाद दोहा के समर्थन को मजबूत करना है। 09 सितम्बर को दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किया गया इजराइली हमला क्षेत्र में बड़े स्तर पर तनाव बढ़ाने वाला साबित हुआ। यह हमला 07 अक्तूबर 2023 के हमास-नेतृत्व वाले हमले और उसके बाद शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। दोहा में आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने हमले को कायराना और विश्वासघाती करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास नेता उस समय अमेरिका द्वारा प्रस्तुत युद्धविराम प्रस्ताव पर कतर और मिस्र के साथ विचार कर रहे थे, जब हमला हुआ।

इजरायल का गाजा सिटी पर बड़ा हमला, आईडीएफ ने पुष्टि की

एजेंसी

गाजा/तेल अवीव। आईडीएफ ने गाजा सिटी में बड़े हमले का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने गाजा सिटी में हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में एक बड़े हमले की शुरुआत की पुष्टि होती है। आईडीएफ के प्रवक्ता (अरबी भाषा) कर्नल अविचाय अद्राई ने एक्स पोस्ट में कहा, गाजा सिटी को एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है, इस क्षेत्र में रहना जोखिम भरा है। नागरिकों को तुरंत क्षेत्र खाली कर गाजा पट्टी के दक्षिण में इजरायल की ओर से चिन्हित मानवीय क्षेत्र की ओर जाने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न स्थानीय मीडिया के हवाले से सिन्हुआ ने भी हमले की जानकारी दी है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए जमीनी हमला किया। इजरायली अखबार द यरूशलम पोस्ट ने पुष्टि की है कि इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) का गाजा शहर पर आक्रमण सोमवार देर रात शुरू

हुआ। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, आईडीएफ हाल के दिनों में शहर और उसके आसपास हवाई हमलों का धीरे-धीरे विस्तार कर रहा है, लेकिन उसने घनी आबादी वाले उत्तरी शहर में जमीनी सैनिकों को नहीं भेजा है।गाजा में स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने गाजा शहर में किसी भी इजरायली टैंक के घुसपैठ से इनकार किया है। गाजा शहर के निवासियों ने कहा कि अभी तक शहर के अंदरूनी हिस्सों में इजरायली टैंकों के प्रवेश या आवाजाही का कोई दृश्य नहीं देखा गया है। लेकिन उन्होंने गाजा शहर के अधिकांश हिस्सों में तीव्र हवाई हमलों और ड्रोन बमबारी की पुष्टि की है। गाजा शहर में हवाई हमलों और बमबारी के बाद, इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि गाजा जल रहा है। काट्ज ने कहा कि आईडीएफ आतंकवादी ढांचे पर कड़ा प्रहार कर रहा है और बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। काट्ज ने आगे कहा, ÷जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता, हम न तो झुकेंगे और न ही पीछे हटेंगे। फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने मंगलवार तड़के बताया कि इजरायली सेना ने सोमवार रात से गाजा शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए, डब्ल्यूएएफए ने कहा कि इजरायली युद्धक विमान लगभग बिना रुके शहर पर हमला कर रहे हैं। इजरायल के आर्मी रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के हफ्तों में, लगभग 3,00,000 फिलिस्तीनी गाजा शहर से भाग गए हैं।

बलोचिस्तान में आईईडी विस्फोट में कैप्टन समेत पांच सैनिक मारे गए

एजेंसी

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान के बलोचिस्तान के केच जिले में सुरक्षा बलों पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से किए गए हमले में एक कैप्टन समेत पांच सैनिक मारे गए। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने सोमवार देररात बताया कि दोपहर के वक्त केच के शेर बांदी में सैनिकों की टुकड़ी के आगे बढ़ने पर आईईडी विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में एक कैप्टन समेत देश के पांच बहादुर सपूतों की जान चली गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए सैनिकों में लोरलाई के 25 वर्षीय कैप्टन वकार अहमद, डेरा गाजी खान के 35 वर्षीय नायक असमत उल्लाह, सुक्कुर के 29 वर्षीय लांस नायक जुनैद अहमद, मर्दन के 29 वर्षीय लांस नायक खान मोहम्मद और स्वाबी के 28 वर्षीय सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। आईएसपीआर ने कहा, हमारे बहादुर अधिकारियों और सैनिकों की शहादत हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर दृढ़ हैं। इससे पहले, 13 और 14 सितंबर को खैबर-पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने एक अभियान में 31 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। सेना की मीडिया शाखा के अनुसार, 10 से 13 सितंबर के बीच खैबर-पख्तूनख्वा में चलाए गए तीन अलग-अलग खुफिया अभियानों में कुल 19 सैनिक मारे गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 45 आतंकवादी मार गिराए।

डोनाल्ड ट्रंप ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर किया 15 अरब डॉलर का मानहानि केस, बताया- 'सबसे गिरा अखबार'

एजेंसी

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अमेरिकी दैनिक समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर 15 अरब डॉलर का मानहानि केस दर्ज कराया है। ट्रंप का आरोप है कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' उनके खिलाफ 'दशकों से झूठ का अभियान' चला रहा है और 'कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी के मुखपत्र' की तरह काम कर रहा है।

ट्रंप ने कहा कि वह 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर 15 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र में उन पर, उनके परिवार, उनके व्यवसायों और उनके राजनीतिक आंदोलन को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने लिखा, आज मुझे 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के खिलाफ 15 अरब डॉलर का मानहानि और मानहानि का मुकदमा दायर करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अखबार हमारे देश के इतिहास के सबसे घटिया और गिरे अखबारों में से एक है और कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी का आभासी 'मुखपत्र' बन गया है।' रिपब्लिकन नेता ने अखबार पर डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के समर्थन का आरोप लगाया और दावा किया कि पहले पन्ने पर उनकी मौजूदगी अब तक का सबसे बड़ा अवैध चुनावी योगदान है।उन्होंने कहा कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' दशकों से आपके पसंदीदा राष्ट्रपति यानी मुझसे, मेरे परिवार, व्यवसाय, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट, एमएजीए (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) और हमारे पूरे देश के बारे में झूठ बोलने का तरीका अपना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को फर्जी समाचार का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम फर्जी समाचार नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि जॉर्ज स्लोपाडोपोलोस/एबीसी/डिज़्नी और 60 मिनट्स/सीबीएस/पैरामाउंट के खिलाफ पहले दायर किए गए हमारे मुकदमे सफल रहे। इन मीडिया संस्थानों ने दस्तावेज और दृश्यों में बदलाव कर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें कलंकित करने की कोशिश की और बाद में रिकॉर्ड रकम पर उन्हें समझौता करना पड़ा।

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की कवरेज को एबीसी और सीबीएस जैसे संस्थानों के समान बताते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इन संगठनों ने लंबे समय से दुर्व्यवहार का एक पैटर्न अपनाया है। यह अस्वीकार्य और अवैध दोनों है। उन्होंने कहा, 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को बहुत लंबे समय से खुलेआम झूठ बोलने, बदनाम करने और मुझे बदनाम करने की छूट दी गई है और अब यह सब बंद हो जाएगा। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' से पहले ट्रंप कई मीडिया संस्थानों से नाराज हो चुके हैं। एबीसी न्यूज ने राष्ट्रपति के साथ अपने एक मुकदमे का निपटारा ट्रंप लाइब्रेरी के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का दान देकर किया था। इसी तरह, सीबीएस की मूल कंपनी पैरामाउंट ने डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के साथ 2024 के एक साक्षात्कार में संपादकीय निर्णयों को लेकर ट्रंप के साथ एक अलग मुकदमे का निपटारा किया।

आईएईए के सम्मेलन में परमाणु अप्रसार योजना के संरक्षण पर जोर, 19 सितंबर तक चलेगी बैठक

एजेंसी

वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का 69वां आम सम्मेलन वियना में शुरू हुआ, जिसमें परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और 'वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की रक्षा' की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।इस बैठक में आईएईए के सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 2,500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह बैठक 19 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान प्रतिनिधि एजेंसी की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट और 2026 के बजट की समीक्षा करेंगे और परमाणु विज्ञान के साथ ही उसके प्रयोगों से लेकर यूक्रेन, मध्य पूर्व और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में सुरक्षा और संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कार्यालय के महानिदेशक गाडा वैली के एक संदेश में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आईएईए यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। इस संदेश में कहा गया, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये उपकरण विकास को आगे बढ़ाएं और मानवता की रक्षा करें। उन्होंने परमाणु प्रसार के खतरे को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण क्षण में आयोजित होने की बात कही। उन्होंने आतंकवाद, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ती वैश्विक असमानता के बीच परमाणु मानदंडों के कमजोर पड़ने का जिक्र किया। समाचार एजेंसी f के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था पर भारी दबाव है और उसे संरक्षण की आवश्यकता है। इससे पहले राफेल ग्रॉसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'हम परमाणु ऊर्जा के मामले में 'सच्चाई की ओर वापसी' भी देख रहे हैं। आंकड़े खुद बयां करते हैः 2050 तक, परमाणु क्षमता 2.5 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 40 देश परमाणु ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, कुछ पहली बार। पहली बार, वर्ल्ड बैंक परमाणु परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तैयार है। इस साल के अंत में, हम ब्राजील के बेलेम में होने वाले सीओपी-30 में यह संदेश देंगे।

रूसी तेल खरीदने से अमेरिका को नुकसान, ट्रेड वार्ता के बीच नवारो का दावा- 'भारत चीन के साथ असहज'

एजेंसी

न्यूयॉर्क। टैरिफ पर मचे विवाद के बीच अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच नई दिल्ली के दौरे पर हैं। लिंच की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब कई दिनों के तीखे गतिरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक संदेशों से व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इस दौरान भारत के सख्त विरोधी रहे ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि रूस से तेल खरीद अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंधों पर असर डाल रही है। सीएनबीसी के कार्यक्रम स्क्वॉक बॉक्स में उन्होंने कहा, भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। नवारो ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण, अच्छा और रचनात्मक पोस्ट किया और राष्ट्रपति

ट्रंप ने उस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने क्रम को गलत समझ लिया है। ट्रंप ने 9 सितंबर को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना महान मित्र बताते हुए कहा कि वह उनसे बात करेंगे। ट्रंप के पोस्ट पर लगभग 17 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ÷मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने आगे कहा था कि वह ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। नवारो ने नई दिल्ली पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत भी दोहराई, जबकि साक्षात्कारकर्ता ने नवारो की उस टिप्पणी का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा बताया।

नवारो ने कहा, किसी भी बड़े देश की तुलना में उनके टैरिफ सबसे ज्यादा हैं। हमें इससे वैसे ही निपटना पड़ा, जैसे हम हर दूसरे देश के साथ निपट रहे हैं, जो ऐसा करता है।उन्होंने दावा किया कि वैसे यह मुद्दा भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने का है, जो यूक्रेन संघर्ष से पहले नहीं था। युद्ध के तुरंत बाद भारतीय रिफाइनर रूसी रिफाइनरों के साथ मिल गए और वे 'डाकुओं' की तरह काम कर रहे हैं।

ट्रंप 19 सितंबर को जिनपिंग से करेंगे बातचीत, टिकटॉक सौदे का खाका तैयार

एजेंसी

वॉशिंगटन/मैड्रिड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह 19 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे। यह वार्ता हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद संभव हो रही है, जिसमें टिकटॉक ऐप को अमेरिका में चलाए रखने के लिए एक ढांचा-समझौता तैयार किया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा - मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी से बात करूंगा। हमारे संबंध अब भी बेहद मज़बूत हैं।अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मैड्रिड में पत्रकारों को बताया कि टिकटॉक पर एक प्रारंभिक समझौता हो गया है और अब ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत से इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बेसेंट के अनुसार, ÷खाका यह है कि टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को अमेरिकी नियंत्रण में लाया जाए। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत टिकटॉक की अमेरिकी शाखा को बेचने की समय सीमा इस हफ्ते समाप्त हो रही है। ट्रंप पहले भी यह समय सीमा कई बार बढ़ा चुके हैं ताकि ऐप को बंद न करना पड़े। ट्रंप मानते हैं कि टिकटॉक ने पिछले चुनाव में युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में भूमिका निभाई थी। सितंबर में वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच उच्च-स्तरीय संपर्क तेज हुए हैं। उम्मीद है कि दोनों नेता अक्टूबर के अंत में दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन में आमने-सामने भी मुलाकात कर सकते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपने चीनी समकक्षों से बातचीत की। दोनों देशों ने फिलहाल एक-दूसरे पर लगाए गए चरम आर्थिक प्रतिबंध निलंबित कर दिए हैं, जिनमें अमेरिकी टैरिफ 145 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए थे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने भी संकेत दिया।

नेपाल में जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन शहीदों के लिए 15 लाख रुपए की राहत की घोषणा

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद, सरकार ने जेन जेड आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया। गृह एवं कानून मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने पुष्टि की कि प्रत्येक शहीद के परिवार को कुल 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार व रसद संबंधी खर्चों के लिए 5 लाख रुपए शामिल हैं। 8 और 9 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा विवादास्पद प्रतिबंध लगाए जाने के बाद शुरू हुए जेन-जेड विरोध प्रदर्शन जल्द ही देशव्यापी अशांति में बदल गए। सेंसरशिप और भ्रष्टाचार

के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके कारण प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनों में 72 लोगों की जान चली गई, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और तीन पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जबकि 1,300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी तक, देश भर में 283 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मंत्री आर्यल ने कहा कि मुआवजा वित्त मंत्रालय के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसका समन्वय गृह मंत्रालय या संबंधित जिला प्रशासन कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार सभी घायलों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करेगी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के लिए उनके गृहनगर तक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शामिल हैं। राज्य अंतिम संस्कार समारोहों में भी सहायता करेगा। जेन ज़ेड आंदोलन को नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, और आर्थिक अवसरों की कमी से प्रेरित होकर, इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन मुख्य रूप से 30 वर्ष से कम आयु के युवा नेपालियों द्वारा किया गया था।

ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की 'ड्रग बोट' पर फिर किया हमला, तीन की मौत

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने दो सप्ताह में दूसरा हमला वेनेजुएला से आई एक कथित ड्रग बोट को निशाना बनाकर किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाज पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज सुबह, मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में स्पष्ट रूप से पहचाने गए, असाधारण रूप से हिंसक ड्रग तस्करी कार्टेल और नार्कोटेररिस्ट के खिलाफ दूसरा काइनेटिक स्ट्राइक किया।' उन्होंने कहा, 'ये बेहद हिंसक ड्रग तस्करी कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा हैं।' ट्रंप के पोस्ट में एक वीडियो भी शामिल है, जिसे 'अनक्लासीफाइड' बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक जहाज में अज्ञात जलक्षेत्र में आग लग गई। इससे पहले 2 सितंबर को ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वेनेजुएला से कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज पर अमेरिकी सैन्य हमले का आदेश दिया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे, जिन्हें ट्रंप ने 'सकारात्मक रूप से पहचाने गए ट्रेन डे अरागुआ (टीडीए) नार्कोटेररिस्ट' बताया। बाद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए उसे 'गैरकानूनी' बताया। समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने वाशिंगटन पर अपने शासन परिवर्तन के प्रयास को उचित ठहराने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के दावों को गढ़ने का आरोप लगाया तथा इस बात पर जोर दिया कि वेनेजुएला कोका की खेती और कोकीन उत्पादन से मुक्त है। वेनेजुएला पक्ष ने अभी तक दूसरे अमेरिकी हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मादुरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संचार के माध्यम तोड़ दिए हैं। उन्होंने इस रुकावट के लिए वाशिंगटन की धमकियों और ब्लैकमेल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के उकसावे के बावजूद वेनेजुएला शांति बनाए रखने में कामयाब रहा है।

ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त होना चाहिएःअमेरिका

एजेंसी

वियना। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था (आईएईए) के वार्षिक महासम्मेलन में कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। उनका कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालांकि, आईएईए ने स्पष्ट किया था कि उसके पास ईरान के किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम का ठोस प्रमाण नहीं है।प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस राइट ने कहा कि यदि ईरान परमाणु हथियारों का रास्ता छोड़ता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय में वापसी का अवसर, प्रतिबंधों से राहत और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। क्रिस राइट ने कहा कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की हर संभावना को पूरी तरह समाप्त करना होगा, जिसमें यूरेनियम संवर्धन और प्लूटोनियम पुनःप्रसंस्करण की सभी क्षमताएं शामिल हैं।

आईएईए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने लगभग 440.9 किलोग्राम यूरेनियम 60 प्रतिशत तक संवर्धित कर लिया है। यह स्तर हथियार-ग्रेड 90 प्रतिशत शुद्धता से थोड़ा कम है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि इसे और संवर्धित किया जाए तो यह 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

गाजा में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया: संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट

एजेंसी

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच ने पहली बार यह निष्कर्ष निकाला है कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के आयोग की 72 पृष्ठों की रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इजराइल ने सात अक्टूबर, 2023 से अब तक चार बार नरसंहार किया है। यह वही तारीख है, जब आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर रक्तपात करते हुए सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। सीएनएन न्यूज चैनल ने इस आयोग की रिपोर्ट प्रसारित की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाई जा रही है। इस समूह पर जानबूझकर ऐसी स्थितियां थोपी गई जो भौतिक विनाश का कारण बनीं। उधर, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय तो पहले से ही दावा कर रहा कि सात अक्टूबर से गाज़ा में लगभग 65,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह मंत्रालय नागरिकों और हमास लड़ाकों में कोई अंतर नहीं करता, लेकिन उसने कहा है कि अधिकतर हताहत महिलाएं और बच्चे हैं।इजराइली सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि वह गाजा में आत्मरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में युद्ध कर रही है। नरसंहार के आरोप बेबुनियाद हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, इजराइल इस विकृत और झूठी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता है और जांच को तुरंत रद्द करने की मांग करता है। बयान में इस जांच को पूरी तरह से हमास के झूठ पर आधारित रिपोर्ट बताया गया

है। यही नहीं जांचकर्ताओं पर उस उग्रवादी समूह का प्रतिनिधि होने का आरोप लगाया है, जिसके यहूदियों के बारे में भयावह बयानों की दुनिया भर में निंदा की गई है। इजराइल वैसे भी कई सालों से इस रिपोर्ट को बनाने वाले मानवाधिकार आयोग पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाता रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल का समर्थन किया है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सीनेटर क्रिस वैन होलेन और जेफ मर्कले ने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गाजा से फिलिस्तीनियों का सफाया करने की योजना लागू कर रही है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। इस महीने की शुरुआत में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स ने कहा था कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। जुलाई में दो प्रमुख इजराइली मानवाधिकार संगठनों ने भी दावा किया था कि उनका देश गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक अभूतपूर्व मामले में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया था। संयुक्त राष्ट्र आयोग की यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब इजराइल ने बढ़ती अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद गाजा शहर पर बमबारी करने के बाद जमीनी घुसपैठ शुरू कर दी है। आयोग की यह रिपोर्ट पूर्वी यरुशलम और फिलिस्तीनी क्षेत्र पर केंद्रित है। आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 में की थी। इसका नेतृत्व नवी पिल्लै कर रहे हैं। वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के पूर्व उच्चायुक्त, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और रवांडा के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण के पूर्व न्यायाधीश और अध्यक्ष हैं।

एसबीआई का जीएमयू कोलकाता से स्थानांतरित किये जाने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

एजेंसी

कोलकाता। कोलकाता स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सर्कल मुख्यालय के बाहर नागरिक मंच 'बैंक बचाओ देश बचाओ मंच' ने विरोध प्रदर्शन किया। मंच ने बैंक के ग्लोबल मार्केट यूनिट (जीएमयू) को कोलकाता से स्थानांतरित करने के निर्णय का विरोध जताया। मंच का आरोप है कि यह कदम पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा और देश की बैंकिंग संरचना में कोलकाता की ऐतिहासिक भूमिका को खत्म करने की कोशिश है। संस्था का कहना है कि इस स्थानांतरण से पश्चिम बंगाल को हर साल 65 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी राजस्व का नुकसान होगा, साथ ही 70 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की आजीविका पर भी संकट आ जाएगा। संस्था के संयुक्त संयोजक बिश्वरंजन राय और सौम्या दत्ता ने साझा बयान में कहा, यह कोई साधारण प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि कोलकाता को उसकी बैंकिंग संरचना में उचित स्थान से वंचित करने की सुनियोजित कोशिश है। फोरम ने यह भी कहा कि कोलकाता एसबीआई के विदेशी कारोबार का केंद्र रहा है। इस विरासत को कमजोर करना, इतिहास और क्षेत्रीय संतुलन, दोनों पर आघात है।

स्टॉक मार्केट में टॉरियन एमपीएस की जोरदार एंट्री, लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी टॉरियन एमपीएस के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 171 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 22.80 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 210 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से इस शेयर की चाल में तेजी आई, जिससे थोड़ी ही देर में ये 220.50 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को करीब 29 प्रतिशत का फायदा हो गया। टॉरियन एमपीएस का 42.53 करोड़ रुपये का आईपीओ 9 से 11 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 11.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 15.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 17.37 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 6.86 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 42.53 करोड़ रुपये के 24,87,200 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में उतार चढ़ाव होता रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 22 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 11.32 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद 2024-25 में कंपनी का शुद्ध लाभ गिर कर 9.50 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के राजस्व में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 10.86 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 44.17 करोड़ रुपये के स्तर पर और वित्त वर्ष 2024-25 में 73.70 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गई। इस दौरान कंपनी पर कर्ज के बोझ में भी उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 14.14 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में कम होकर 7.17 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज बढ़ कर 9.11 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें, तो वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी में ये 1.98 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी में बढ़ कर 13.29 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी में उछल कर 27.90 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

देश का निर्यात अगस्त में 6.7 फीसदी बढ़कर 35.1 अरब डॉलर पर

एजेंसी

नई दिल्ली। देश का निर्यात अगस्त महीने में 6.7 फीसदी बढ़कर 35.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि आयात 10.12 फीसदी घटकर 61.59 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी व्यापार आंकड़ों में बताया कि अगस्त महीने में देश का व्यापार घाटा 26.49 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 35.64 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने देश ने कुल 35.1 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 32.89 अरब डॉलर रहा था। इस दौरान देश का आयात घटकर 61.59 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल के समान महीने में 68.53 अरब डॉलर था। मंत्रालय के मुताबिक अगस्त माह के बेहतर प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पांच महीनों के दौरान देश का कुल निर्यात 184.13 अरब डॉलर हो गया, जबकि इस दौरान कुल आयात 306.52 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इन व्यापार आंकड़ों पर कहा कि वैश्विक और व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के निर्यातकों ने मजबूत और शानदार प्रदर्शन किया है।

स्टॉक मार्केट में वशिष्ठ लग्जरी फैशन की मजबूत एंट्री, आईपीओ निवेशक खुश

नई दिल्ली। हैंड एंब्रायडरी वर्क और इससे जुड़ी एक्सेसरीज तथा तैयार कपड़े बना कर निर्यात करने वाली कंपनी वशिष्ठ लग्जरी फैशन के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। हालांकि, लिस्टिंग के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशकों को झटका भी लगा, क्योंकि बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयर गिर कर लोअर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही खरीदारी शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयरों ने लोअर सर्किट ब्रेक करके मजबूती हासिल कर ली। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 111 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 6.31 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 118 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयर गिर कर 112.10 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक आ गए। इसके थोड़ी देर बाद खरीदारी शुरू जाने के कारण इसकी स्थिति सुधरी। पूरे दिन के कारोबार के बाद कंपनी के शेयर 120.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस तरह पहले दिन के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 8.56 प्रतिशत का मुनाफा हो गया।

स्टॉक मार्केट में कार्बनस्टील की जोरदार एंट्री, लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। स्टील के भारी-भरकम प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली कंपनी कार्बनस्टील इंजीनियरिंग के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 159 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 16.42 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 185.10 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से इस शेयर की चाल में और तेजी आ गई, जिससे थोड़ी ही देर में ये 194.35 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 22.23 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है।

कार्बनस्टील इंजीनियरिंग का 59.30 करोड़ रुपये का आईपीओ 9 से 11 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये

ओवरऑल 76.59 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 121.61 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 85.99 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 46.84 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 48.33 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 6.90 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी अंबरगांव फैसिलिटी में नया शेड तैयार करने, अपने पुराने कर्ज को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 5.11 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 9.42 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 14.16 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

क्रृपालु मेटल्स ने आईपीओ निवेशकों को किया निराश, कमजोर लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। तांबा और पीतल के शीट, पट्टी और रॉड बनाने वाली कंपनी क्रृपालु मेटल्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 72 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 57.60 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण कंपनी के शेयर थोड़ी ही देर में गिर कर 54.72 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर आ गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही क्रृपालु मेटल्स के आईपीओ निवेशकों को 24 प्रतिशत का नुकसान हो गया।

क्रृपालु मेटल्स का 13.48 करोड़ रुपये का आईपीओ 8 से 11 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 2.96 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन

में 6.45 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.85 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 18.72 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपना नया प्लांट लगाने और मशीनरी की खरीदारी करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 42 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 1.55 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 2.15 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 20 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 48.50 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी पर कर्ज में उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 7.44 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 9.57 करोड़ रुपये हो गया।

भारत की विकास यात्रा में स्थिरता पर कोई समझौता नहीं: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में स्थिरता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक मानकों में सामंजस्य से गुणवत्ता, मुक्त व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) की 89वीं आम बैठक एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। गोयल ने 'एक सतत विश्व को बढ़ावा देना' विषय पर बोलते हुए स्थिरता, सुरक्षा और दक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत के लिए स्थिरता पर कोई समझौता नहीं है और मानक उपभोक्ता सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मकता और जलवायु उत्तरदायित्व के लिए एक रणनीतिक माध्यम हैं। गोयल ने कहा कि सरकार गुणवत्ता और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नीलाचल कार्बो के शेयरों पर अपर सर्किट के बावजूद निवेशक नुकसान में

एजेंसी

नई दिल्ली। हाई क्वालिटी और लो सल्फर वाले मेटलर्जिकल कोक बनाने वाली कंपनी नीलाचल कार्बो मेटलिक्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में कमजोर एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 85 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 68 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से इस शेयर की चाल में तेजी आई, जिससे थोड़ी ही देर में ये 71.40 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में अपर सर्किट लगने के बावजूद कमजोर लिस्टिंग के कारण कंपनी के आईपीओ निवेशक अभी भी 16 प्रतिशत के नुकसान में हैं।

नीलाचल कार्बो मेटलिक्स का 56.10 करोड़ रुपये का आईपीओ 8 से 9 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 5.06 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 4.56 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 5.55 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 22.10 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 40 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी कोक ओवन प्लांट लगाने, मौजूदा प्लांट का आधुनिकीकरण करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में उतार चढ़ाव होता रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 14.82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 15.82 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद 2024-25 में कंपनी का शुद्ध लाभ गिर कर 14.02 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के राजस्व में भी गिरावट दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 268.46 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में गिरकर 267.13 करोड़ रुपये के स्तर पर और वित्त वर्ष 2024-25 में 202.79 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गई। इस दौरान कंपनी पर कर्ज के बोझ में भी उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 18.84 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 26.14 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज घट कर 23.55 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें, तो यह वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी में ये 26.14 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी में बढ़ कर 41.95 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी में उछल कर 55.97 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच आज रात भारत पहुंचेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए आज रात भारत पहुंचेंगे। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (बीटीए) पर छठे दौर की बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत संवेदनशील कृषि और डेयरी बाजारों तक पहुंच को लेकर रुकी हुई थी। अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम के आज भारत पहुंचने की संभावना है। उनके आने पर यह बातचीत फिर से शुरू होगी। ब्रेंडन लिंच अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) हैं। ये बातचीत ऐसे समय में होने जा रही है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 फीसदी

टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, ट्रंप प्रशासन रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की नियमित रूप से आलोचना करके यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है।

आयकर विभाग ने आईटीआर की समय सीमा बढ़ाने की खबरों को बताया अफवाह

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। विभाग ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने आईटीआर भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। आयकर विभाग ने जारी एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर चल रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक @IncomeTa&India अपडेट पर ही भरोसा करें। आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इंडिगो और एजियन ने कोडशेयर साझेदारी के लिए किया समझौता

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की बजट एयरलाइन इंडिगो और ग्रीस की प्रमुख एयरलाइन एजियन ने अपने संयुक्त नेटवर्क पर ग्राहकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कोडशेयर साझेदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिगो ने जारी बयान में कहा कि इस सहयोग से दोनों एयरलाइन कंपनियां एक-दूसरे के नेटवर्क पर उड़ानें संचालित कर सकेंगी, जिससे एजियन भारत और दक्षिण एशिया में अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकेगा। इसके साथ ही इंडिगो के ग्राहकों के लिए अपने व्यापक घरेलू और यूरोपीय नेटवर्क पर अधिक यात्रा विकल्प को उपलब्ध करा सकेगा। ये नियामक अनुमोदन के अधीन है। बयान के मुताबिक इस साझेदारी के माध्यम से एजियन ग्राहकों को भारत और दक्षिण एशिया के गंतव्यों तक

व्यापक पहुँच प्राप्त होगी, क्योंकि एयरलाइन का उड़ान कोड 3 इंडिगो के नेटवर्क पर कई गंतव्यों में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो का 6E उड़ान कोड एजियन की घरेलू और यूरोपीय उड़ानों में एथेंस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसके मुख्य केंद्र से जोड़ा जाएगा। ये साझेदारी भारत, ग्रीस और दक्षिण एशिया के बीच ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा और निर्बाध यात्रा की अनुमति देगी। एकीकृत यात्रा कार्यक्रम के साथ, ग्राहक अन्य लाभों के साथ-साथ चेक-इन प्रक्रिया का भी आनंद ले सकेंगे। कोडशेयर मार्गों के बारे में अतिरिक्त विवरण समय पर प्रदान किए जाएंगे।

इंडिगो ने जनवरी 2026 से एथेंस के लिए सीधी उड़ानें संचालित करने की अपनी योजना का ऐलान किया है, जबकि दूसरी ओर एजियन ने मार्च 2026 तक भारत के लिए उड़ानों की घोषणा की है।

इंडिगो एथेंस के लिए छह साप्ताहिक उड़ानों से शुरुआत करेगी, जबकि एजियन दिल्ली के लिए पांच साप्ताहिक उड़ानें और उसके बाद मुंबई के लिए 3 साप्ताहिक उड़ान सेवाएं शुरू करेगा।

अबतक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर हुआ दाखिल :आयकर विभाग

एजेंसी

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा कि अब तक 7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने यह बात इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत और समय-सीमा बढ़ाने की मांग के बीच कही है। आयकर विभाग ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि अबतक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं और गिनती अभी भी जारी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा हो समाप्त होने के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में आयकरदाताओं ने रिटर्न भरने के लिए लॉगिन किया। विभाग ने कहा कि हम इस उपलब्धि तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और हम उन सभी से

आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, कि वे अपना आयकर रिटर्न फाइल करें। आयकर विभाग ने कहा है कि आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर कार्यरत है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के जरिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।

अगस्त महीने में यात्री वाहनों की थोक बिक्री नौ फीसदी घटी: सियाम

एजेंसी

नई दिल्ली। अगस्त महीने में कुल यात्री वाहन थोक बिक्री (डीलरों को भेजी गई) सालाना आधार पर लगभग 9 फीसदी घटकर 3,21,840 इकाई रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,52,921 इकाई थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने जारी आंकड़ों में बताया कि संख्या में गिरावट की मुख्य वजह यात्री वाहन निर्माताओं के डिस्पैच पुनर्निर्धारण के कारण हुई। हालांकि, अगस्त महीने के दौरान कुल दोपहिया वाहनों की डिस्पैच साल फीसदी बढ़कर 18,33,921 इकाई हो गई, जबकि अगस्त 2024 में यह 17,11,662 इकाई थी। इस अवधि में मोटरसाइकिलों की बिक्री 4.3 फीसदी बढ़कर 11,06,638 इकाई हो गई (अगस्त, 2024 में 10,60,866 इकाई के मुकाबले), स्कूटरों की बिक्री करीब 13 फीसदी बढ़कर 6,83,397 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 6,06,250 इकाई थी। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि ग्राहकों ने जीएसटी दर में कटौती और वाहनों की कीमतों में कमी की उम्मीद में खरीदारी स्थगित कर दी है, जिसकी वजह से अगस्त की मांग में गिरावट आई। मेनन ने कहा कि वाहनों पर जीएसटी दरें कम करने के सरकार के फैसले से आगामी त्योहारी सत्र में मांग बढ़ेगी।

उतार-चढ़ाव के बाद लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में पिछले सप्ताह से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। घरेलू शेयर बाजार पूरे दिन सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद कमजोरी के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद से ही लिवालों और बिकवालों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी की चाल भी लगातार ऊपर नीचे होती रही। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.15 प्रतिशत और निफ्टी 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान एनर्जी, रियल्टी और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। इसी तरह टेक, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.66 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के बावजूद मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में हुई खरीदारी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 460.16 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले सप्ताह के आखिरी

कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 458.72 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया।

आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,389 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,340 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,880 शेयरों में गिरावट का रुख रहा और 169 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,822 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,539 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,283 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 10 शेयर बढ़त के साथ और 20 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 15 शेयर हरे निशान में और 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 20.81 अंक की मामूली तेजी के साथ 81,925.51 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही लिवालों और बिकवालों के बीच एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक 93.81 अंक की मजबूती के साथ 81,998.51 अंक तक पहुंचा, वहीं बिकवाली का दबाव बनने पर इसने 160 अंक की कमजोरी के साथ 81,744.70 अंक तक गोता भी लगाया। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 118.96 अंक की कमजोरी के साथ 81,785.74 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

जब श्रुति हासन पर घर में घुसकर किया गया हमला, शख्स ने पकड़ ली थी गर्दन

फिल्मी सितारों से जुड़ी अक्सर ही ऐसी खबरें भी आती रहती हैं जो उनके फैंस को हैरान कर देती हैं. आज हम आपको साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रुति हासन से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब श्रुति की जान तक पर बन आई थी. सालों पहले एक शख्स एक्ट्रेस के घर में घुस गया था और उनके साथ बदसलूकी की थी. उस शख्स ने श्रुति की गर्दन तक पकड़ ली थी. आइए जानते हैं कि ये घटना कब हुई थी और इसमें श्रुति ने कैसे अपनी जान बचाई थी ?

श्रुति के घर में घुस गया था शख्स

हम जिस घटना के बारे में आपको बात रहे हैं वो साल 2012 की है. उस वक्त श्रुति अपने मुंबई स्थित घर पर थीं. एक दिन सुबह एक्ट्रेस जब सो रही थीं उसी वक्त एक सरफिरा फैन उनके घर में घुस गया था जो कई दिनों से एक्ट्रेस का लगातार पीछा कर रहा था. शख्स ने घर में घुसते ही डोर बेल बजाई.

शख्स ने पकड़ ली थी एक्ट्रेस की गर्दन

श्रुति उस वक्त सो रही थीं और उनकी नींद पूरी तरह नहीं खुल पाई थी. एक्ट्रेस ने डोर बेल बजने के बाद आकर दरवाजा खोला और देखा कि एक शख्स उनके सामने खड़ा है. वो कहने लगा कि उन्होंने उसे पहचाना या नहीं ? इसके आगे शख्स ने कहा था कि आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रही हैं ? इसके बाद उसने श्रुति की गर्दन पकड़ ली थी.

एक्ट्रेस ने इस तरह बचाई थी जान

शख्स की इस हरकत से श्रुति की जान तक पर बन आई थी. हालांकि एक्ट्रेस ने उस वक्त समझदारी से काम लिया और दरवाजा जोर से शख्स के हाथ पर दे मारा. उसने अंदर घुसने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और फिर वहां से भाग गया. इसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत की थी.

बॉलीवुड में भी किया काम

श्रुति हासन साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर कमल हासन और एक्ट्रेस सारिका की बेटी हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में उन्होंने काम किया है. श्रुति 'डी-डे', 'रमैय्या वस्तावैया', 'गब्बर इज बैक', 'वेलकम बैक' और 'रॉकी हैंडसम' जैसी कई फिल्मों में नजर आई हैं.

'राइज एंड फॉल' शो में धनश्री वर्मा ने पवन सिंह को दे दी चुनौती

अमेजन एमएक्स प्लेयर पर इन दिनों 'राइज एंड फॉल' रिएलिटी शो चल रहा है. इस शो अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. इस शो में धनश्री वर्मा और पवन सिंह समेत कई सितारे बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, जो जीत के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में लगे हैं. हाल ही में धनश्री वर्मा ने इस शो में सभी कंटेस्टेंट्स के सामने पवन सिंह को खुलेआम चुनौती दे दी.धनश्री वर्मा के इंस्टाग्राम आई पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में

लिखा गया, पवन जी, तारीफ करोगे तो ये मतलब नहीं कि ये शेर शिकार करना भूल जाएगा.

धनश्री ने ये कैप्शन कुछ भोजपुरी में लिखने की कोशिश की जो काफी मजेदार था. इस वीडियो में धनश्री पवन सिंह के लिए क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि धनश्री कई कंटेस्टेंट्स के साथ बैठी हैं, जिनमें पवन सिंह भी शामिल हैं. पवन सिंह को देखकर धनश्री मारने का इशारा करती नजर आई.

फिर बोलीं, मैंने पवन जी से कल रात को बोला अब मैं आपसे ही झगड़ा करूंगी पूरे हफ्ता भर. ये सुनकर पवन सिंह ने कहा, तो शुरू कहां से करना है, गाली गलौच या सिर्फ बात करके ? इसपर धनश्री ने जवाब दिया, गाली-गलौच मैं नहीं कर सकती. तो पवन सिंह ने कहा, तो बात में झगड़ा कैसे होगा, कैसे मजा आएगा ?

इसपर धनश्री ने कहा, वो हाथ दिखाते हुए ऐसे-ऐसे करते हैं न वैसे करेंगे और क्या. पवन सिंह मुंह पर हाथ रखकर हंसे और फिर बोले, तो फिर नाम के आगे जी क्यों लगाने का, पवन पे आइए पहले. इसपर धनश्री ने कहा, नहीं रिस्पेक्ट तो देनी होगी न. झगड़ा तो मां-बाप से भी होता है, लेकिन रिस्पेक्ट थोड़ी भूली जाती है. ये सुनकर पवन सिंह दूसरे कंटेस्टेंट आदित्य नारायण की तरफ देखते हुए बोले, क्या लड़की के अंदर गुण है यार, संस्कार तो है इसमें.

वो एक्ट्रेस, जिसने दान कर दी पहली फिल्म की कमाई, पिक्चर ने बटोरे थे 215 करोड़

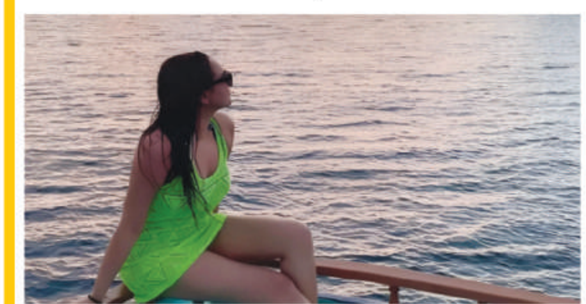

आज बात बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना की करेंगे, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में धमाका कर दिया था. पहली ही फिल्म से ये एक्ट्रेस स्टार बन गई थीं. उनकी डेब्यू पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर 15 साल पहले 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और उन्हें भी फिल्म के लिए अच्छी फीस मिली थी. लेकिन, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी पहली फिल्म से हुई कमाई को दान कर दिया था. ये एक्ट्रेस है 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा.सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दबंग' से की थी. दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा की बेटी सोनाक्षी के अपोजिट उनकी पहली पिक्चर में सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया था. डेढ़ दशक पुरानी ये फिल्म आज भी लोग बड़े चाव के साथ देखना पसंद करते हैं.

सोनाक्षी ने कहां दान की थी अपनी कमाई ?

जहां सलमान खान फिल्म में सोनाक्षी के हीरो थे तो वहीं सलमान के छोटे भाई और अभिनेता अरबाज खान ने दबंग को प्रोड्यूस किया था. बताया जाता है कि सोनाक्षी ने अपनी डेब्यू फिल्म की कमाई को सलमान खान के चैरिटेबल फाउंडेशन 'बीइंग ह्यूमन' को दान में दे दिया था.

बनी थी 2010 की सबसे कमाऊ फिल्म

दबंग में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अरबाज खान, सोनू सूद, माही गिल, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना और टीनू आनंद जैसे कलाकारों ने भी काम किया था. अभिनव कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म पर मेकर्स ने 42 करोड़ रुपये खर्च किए थे. जबकि फिल्म ने भारत में 140 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. वहीं वर्ल्डवाइड 215 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था. इस हिसाब से दबंग साल 2010 की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी.

सोनाक्षी सिन्हा का वर्कफ्रंट

दबंग से ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने 'राउडी राठौड़' और 'सन ऑफ सरदार' जैसी बेहतरीन फिल्में भी दी हैं. 37 वर्षीय सोनाक्षी अब भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. हाल ही में उन्हें फिल्म 'निकिता रॉय' में देखा गया था. लेकिन, ये पिक्चर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी. इसका डायरेक्शन सोनाक्षी के भाई कुश सिन्हा ने किया था.

देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया यार तू... 23 साल के हुए आरव, पापा अक्षय कुमार ने किया इमोशनल पोस्ट

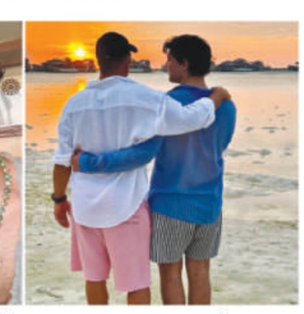

इस साल 9 सितंबर को बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपना 58वां बर्थडे मनाया है. सितंबर के महीने में ही अक्षय कुमार के बेटे आरव का बर्थडे भी होता है और आज यानी 16 सितंबर को वो खास दिन मनाया जा रहा है. अक्षय कुमार के बेटे आरव आज 23 साल के हो गए हैं और बेटे के लिए पापा अक्षय ने एक खास पोस्ट लिखा और एक लेटेस्ट तस्वीर भी शेयर की है. अक्षय कुमार ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उनके बेटे बिल्कुल यंग अक्षय दिख रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ वाली तस्वीर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने पोस्ट लिखा है. पोस्ट में अक्षय कहते हैं, 'हैप्पी 23 साल आरव, जब मैं 23 साल का था तब लोगों को स्क्रीन पर बीट करना सीख रहा था. अब ये देखना एक अजीब एहसास है कि तकनीक से लेकर फैशन तक और खाने की मेज पर बहस तक, तुम मुझे रोज बीट कर रहे हो. देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है यार तूमेरी कहानी में तुम मुझे प्राउड महसूस कराते हो, लव यू बेटा. मेरी लाइफ के बेस्ट 23 साल के लिए शुभकामनाएं, जिनमें तुम मेरे साथ रहे.'

इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में ज्यादातर फैंस आरव को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. वहीं एक फैन ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे जूनियर खिलाड़ी.', किसी दूसरे फैन ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे आरव, भगवान तुम्हें खुशियां और कामयाबी दे, तुम अपने पापा की तरह खूब आगे बढ़ो.' वहीं एक फैन ने लिखा, 'सर, आपका बेटा जूनियर अक्षय कुमार बनेगा ? वैसे ये आपकी तरह ही है, हैप्पी बर्थडे आरव.' इसी तरह से फैंस ने कमेंट में सवाल भी किए और अच्छे-अच्छे कमेंट लिखकर बर्थडे विश भी किया.

आरव का 15 सितंबर 2002 को मुंबई में जन्म हुआ था. वो लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं. हालांकि फिर भी पैपराजी के कैमरो में वो कई बार कैद हो जाते हैं. 2024 में आए शिखर धवन के टॉक शो में अक्षय कुमार ने बताया था कि आरव अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं.

आरव करियर में क्या करना चाहते हैं, इसपर सवाल हुआ तो अक्षय कुमार ने कहा था कि ये पूरी तरह आरव पर निर्भर करता है. वो जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है ये उनकी चाहत होगी और बतौर पिता अक्षय अपने बेटे का पूरा सपोर्ट करेंगे. आरव सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं, लेकिन जब भी उनकी तस्वीर कहीं से आती है तो उनका लुक काफी वायरल होता है.

प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रस्तावक रहे पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्र की स्थिति में सुधार

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रस्तावक रहे पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र को हार्ट अटैक आने के बाद 13 सितंबर को गंभीर अवस्था में सर सुंदरलाल अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। मंगलवार की सुबह चिकित्सकों की टीम ने छन्नूलाल मिश्र की स्थिति में सुधार होने की जानकारी दी है। सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार ने बताया कि प्रसिद्ध संगीतकार पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र को डायबिटीज मेलीटस, हाइपरटेंशन, आस्टियो आर्थराइटिस, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरपलासिया जैसी गंभीर बीमारियां है।

अस्पताल में रहते हुए छन्नू लाल मिश्र का एक्यूट रेस्पीरेटरी, डिस्ट्रेस सिंड्रोम और डीप वेन थ्रांबोसिस का इलाज भी हुआ है। छन्नूलाल को नान इनवेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। कुशल चिकित्सकों की एक टीम सुबह-शाम उनका उपचार कर रही है।

सपा भाजपा के नेताओं ने छन्नू लाल मिश्र का जाना कुशलक्षेम

सर सुंदरलाल अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्र का कुशलक्षेम जानने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल मोहले सहित तमाम सपा भाजपा के नेता पहुंच चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रस्तावक रहे है छन्नू लाल मिश्र

आजमगढ़ में जन्मे और बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले गायकी के सरताज प्रसिद्ध संगीतकार छन्नू लाल मिश्र वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रस्तावक रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

GST पर बोले भाटिया मेडिकोस के मालिक: दवाओं पर टैक्स से जनता को मिली राहत

मनीषा

दिव्य दिल्ली : देश में 2017 में लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर (GST) आठ साल बाद एक बड़े सुधार से गुजरा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। अब पूरे सिस्टम में केवल दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे - 5% और 18%। सरकार का कहना है कि इस कदम से टैक्स प्रक्रिया आसान होगी और कारोबारियों पर जटिलता का बोझ कम होगा। जिसके चलते लोगों की राय जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के रघुवीर नगर भाटिया मेडिकोस जहा हमारी मुलाकात हुई शॉप के ऑनर से जिन्होंने (GST) कम होने को ले कर अपनी राय बताई और ये भी बताया की दवाइयों पर (GST) कम होने से दुकानदारों और उपभोक्ताओं को कितना फयफा होगा।और साथ ही जिन चीजों पर अभी तक (GST) कम नहीं की गई है। सरकार को उन चीजों पर भी (GST) कम करनी चाहिए।

श्याम लाल यादव हमारे लिए लौह पुरुष और कमजोरों की आवाज थे - वैश्य नटवर गोयल

लखनऊ

स्व. बाबू जी श्याम लाल यादव जी की 99वीं जयंती के पावन अवसर पर, आज गर्दे सभागार, पराड़कर भवन, मैदागिन, वाराणसी में आयोजित भव्य जयंती समारोह में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल सम्मिलित होकर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन किया।

अपने शब्दों में कहां की बाबूजी सदैव समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों की आवाज बनकर खड़े रहे। उनके संघर्षों और योगदान ने सामाजिक न्याय की अलख जगाई, जो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। समारोह में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया एवं उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसी के साथ ही उन्होंने भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के 165 वे जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए नमन किया और कहां की आज पूरा देश उनके नाम पर इंजीनियर डे मना रहा है । एम विश्वेश्वरैया का योगदान भारत के लिए अतुल्य है । भारतीय इंजीनियर हमारे देश के निर्माण में और दुनिया के निर्माण में अभूतपुर योगदान रहा है ।

भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया भारत में टेक्नोलॉजी के ध्वजवाहक थे। इन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है। आज जो बदलाव भारत की हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसकी नीव एम विश्वेश्वरैया ने रखी थी ।

सीएम योगी आदित्यनाथ से की भाजपा जिला अध्यक्ष ने मुलाकात

लखनऊ

भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और उनके सामने लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू की जा रही आवासीय योजनाएं वरुण विहार, प्रबंध नगर नैमिष नगर में अधिकृत भूमि में किसानों को दिए जा रहे मुआवजा को लेकर बात की। मुख्यमंत्री ने योजनाओं में किसनों को एक समान मुआवजा देने की बात की। मुलाकात के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव मौजूद रहे।

जिले की 02 शिक्षिकाएं राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित

हरदोई। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ ने सप्तम राज्य स्तरीय कहानी सुनाओ प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें 75 जनपदों के सर्वश्रेष्ठ चयनित लगभग 150 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वी पी सिंह ने बताया कि हरदोई जिले के प्राथमिक विद्यालय जामू (संडीला) की प्रियंका जायसवाल तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अटवा की तलतजहाँ का चयन राज्य स्तरीय पुरुस्कार के लिए किया गया है। इसके पूर्व पूर्व प्रियंका जायसवाल को उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लिए एचसीएल से बेस्ट टीचर अवार्ड, डीएम हरदोई द्वारा महिला सशक्तिकरण अवार्ड समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

50 हजार का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार सुबह एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी टीम और बिधूना थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना बिधूना क्षेत्र के ग्राम डहरियापुर मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब बीते दिनों ग्राम शामपुर रोड पर अवैध गौवंश से भरे कंटेनर के पलटने की घटना के बाद गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में वांछित 50,000 रुपये का इनामी अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र सुरेश चन्द्र यादव निवासी ग्राम सामपुर, थाना बिधूना जनपद औरैया की तलाश की जा रही थी।

औरैया: सड़क हादसे में युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में रविवार की देर शाम अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर नहर के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक अभी भी आगरा के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

जानकारी के मुताबिक, अड्डा बडेरा निवासी लज्जाराम अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गए थे। रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे उनका 25 वर्षीय पुत्र भूरे बाइक से फुटेकुआ उन्हें लेने जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे 18 वर्षीय सोहित पुत्र शिवराज निवासी जगनपुर की बाइक से उसकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सोमवार शाम भूरे की मौत हो गई। दूसरी ओर, सोहित की हालत गंभीर बनी हुई है, जिस कारण परिजनों ने उसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब भूरे का शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

क्या हादसा होने के बाद ही सचेतेगा बिजली विभाग, काकोरी पावर हाउस से बड़ी लापरवाही आई सामने

लखनऊ

राजधानी शहर लखनऊ में बिजली उपभोक्ता किस तरह हो रहे हैं परेशान । खुले ट्रांसफार्मर का दहशत सता रहा है काकोरी के लोगों को। आपको बता दे पूरा मामला मलिहाबाद डिवीजन के अंतर्गत काकोरी पावर हाउस का है। भाजपा जिला अध्यक्ष कार्यालय के ठीक सामने पहिया आजमपुर गांव हरदोई रोड के किनारे खुला ट्रांसफार्मर मौत को दावत देता आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते है। ना ही कोई सुरक्षा कवच ना ही फेसिंग। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री का कहना है कि बिजली विभाग में साधन संसाधन की कतई कमी नहीं है। उसके बाद भी खुले ट्रांसफार्मर का यह हाल। आखिर बिजली विभाग में मेंटेनेंस पर लाखों रुपए जाता कहां है? पहिया आजमपुर गांव के क्षेत्र वासियों ने बिजली विभाग की शिकायत करते हुए आडे हाथों लिया और खूब खरी खोटी सुनाई।

बहन का सुहाग उजाड़ने वाला 25 हजार का इनामिया मुठभेड़ में घायल

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत स्डौत कोतवाली क्षेत्र के सोनू हत्याकांड में फरार 25 हजार के इनामी हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। सोनू हत्या मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। हत्यारोपी मोहन ने साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा सोनू की हत्या कर बहन का सुहाग उजाड़ दिया था। पुलिस ने मोहन को अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

बडौत में नहर के पास सोनू नाम के युवक का शव मिला था। सोनू को दो गोली मारी गयी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। सोनू के पिता ने सोनू के साले के खिलाफ मामले की शिकायत दी थी। पुलिस जांच में सोनू के साले मोहन ओर उसके दो साथियों के नाम सामने आए थे। शुक्रवार की रात्रि पुलिस मुठभेड़ में मोहन के दो साथी सोनू उर्फ काली और रोहित को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था पूछताछ में दोनों ने बताया था कि मोहन की बहन ज्योति के साथ उसके पति सोनू ने कई बार शराब पीकर मारपीट की थी जिसका बदला लेने के लिए सोनू की हत्या की गई। हत्या के मामले में मोहन फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया।। पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान मोहन को भी गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में मोहन को पैर में गोली लगी है मोहन के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा जरूरी कानूनी कारवाई की जा रही है।

प्रदेशभर में 17 सितंबर से चलेगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह, आंख समेत होंगी विभिन्न जांचें

लखनऊ। योगी सरकार ने महिलाओं, बेटियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में नई पहल की शुरूआत की है। इसके तहत सीएम योगी के निर्देश पर 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश भर में 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, पोषण जागरूकता और मातृत्व लाभ वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इसका उद्?देश्य महिलाओं और उनके परिवार का स्वास्थ्य मजबूत कर समाज को मजबूत करना है।

कैंसर समेत होंगी विभिन्न तरह की जांचें, आयुष्मान कार्ड का किया जाएगा वितरण

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसमें महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ पोषण जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ भी वितरित किया जाएगा। अभियान के स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं के रक्तचाप, मधुमेह, दांत, आंख और ईएनटी की जांच की जाएगी। इसके अलावा कैंसर (मुख, स्तन और ग्रीवा), गर्भवती महिलाओं आदि की जांच की जाएगी।

साथ ही एनीमिया के स्तर, टीकाकरण, टेलीमानस सुविधाएं और सिकल सेल परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पोषण ट्रैकिंग का पंजीकरण भी किया जाएगा।

स्वस्थ जीवनशैली और पोषण पर दिया जाएगा जोर

अभियान के तहत लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें मोटापे को कम करने चीनी और तेल के प्रयोग को 10 प्रतिशत तक कम करने, स्थानीय और मौसमी भोजन को बढ़ावा देने तथा बच्चों, किशोरियों के आहार व आयरन सेवन को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा टेक होम राशन का वितरण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अभियान में प्रदेश के हर नागरिक को भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें रक्तदान शिविर, मित्र स्वयंसेवी पंजीकरण और आंगनबाड़ी पंजीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से आमजन को अभियान से जोड़ा जाएगा।

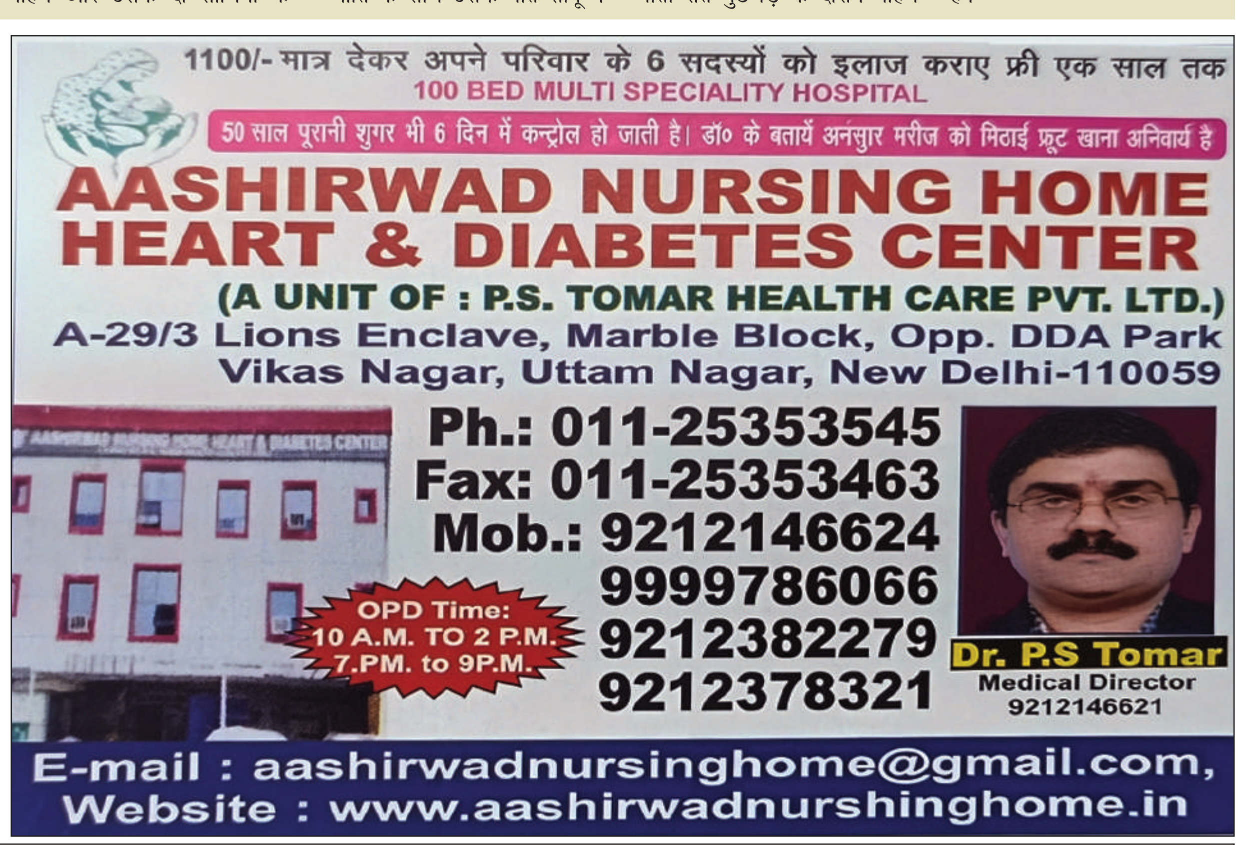

Published, printed and owned by Rajesh. Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi —110063 Editor Rajesh. Chauhan. E mail ID rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321